घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 242- शुक्रवार 03- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा...ऊर्जा स्थिरता...एआई के क्षेत्र में करेंगे सहयोग...

सुजुकी दो-तिहाई कारें भारत में बना रही...जापान की मदद से देश में खाद के 1000 कारखाने लगेंगे : पीएम मोदी

नई दिल्ली,02 जुलाई 2026। भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत-जापान जॉइंट इकोनोमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी कंपनियों की दिक्कतें दूर करने के लिए 'जापान बिजनेस वीक' शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत पीएमओ के सीनियर अधिकारी सीधे जापानी निवेशकों से बातचीत करेंगे। मोदी ने कहा कि आज दुनिया में बिकने वाली सुजुकी की दो-तिहाई कारें भारत में बन रही हैं और इन्हें 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जापान के सहयोग से देश में करीब 1000 खाद (फर्टिलाइजर) कारखाने लगाए जाएंगे। दोनों देशों ने अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश का लक्ष्य भी रखा है। पीएम मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने साने ताकाइची को अपनी'छोटी बहन' कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की तकनीक, निवेश और उत्पादन क्षमता का मेल दोनों देशों के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।

भारत-जापान के बीच 129 समझौतों का ऐलान

भारत-जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में 129 समझौता ज्ञापनों का ऐलान किया गया। इन समझौतों का मकसद दोनों देशों के बीच निवेश,उद्योग,मैन्युफैक्चरिंग,तकनीक,कौशल विकास और सप्लाई चेन सहयोग को मजबूत करना है। इसके साथ ही,भारत में 2 ट्रिलियन जापानी येन (1.18 लाख करोड़ रुपए) से अधिक के भारी निवेश की घोषणा की गई है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में 88 हजार करोड़ जापानी निवेश

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहले अनुमानित लागत करीब 2 लाख करोड़ है। इसमें से लगभग 88 हजार करोड़ जापान दे रहा है। यह पैसा जापान की सरकारी एजेंसी JICA बेहद सस्ती शर्तों पर दे रही है। इस कर्ज पर सिर्फ 0.1% सालाना ब्याज लगेगा,इसे चुकाने के लिए 50 साल मिलेंगे और पहले 15 साल तक किस्त नहीं देनी होगी। जापान अब तक इस परियोजना के लिए 1,150 अरब येन (करीब 55 हजार करोड़) मंजूर कर चुका है। इसके अलावा वह बुलेट ट्रेन की शिंकानसेन तकनीक,ट्रेनिंग और तकनीकी विशेषज्ञता भी भारत को उपलब्ध करा रहा है।

सुजुकी की सालाना 30 में से 20 लाख कार भारत में बन रही...

सुजुकी दुनिया में हर साल करीब 30 लाख (3 मिलियन) कारें बनाती है। इनमें से लगभग 20 लाख (2 मिलियन) कारें अकेले भारत में बनती हैं। यानी कंपनी की हर 3 में से 2 कारें (करीब 66%) भारत में तैयार होती हैं। भारत में ये कारें मारुति सुजुकी के हरियाणा और गुजरात के प्लांट में बनती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में मारुति सुजुकी ने 20 लाख से अधिक कारों का उत्पादन किया और 3 .32 लाख से ज्यादा कारें 100 से अधिक देशों में निर्यात कीं।

भारत के राजस्थान में 'मिनी जापान'

राजस्थान के अलवर जिले के नीमराना को भारत का 'मिनी जापान' या 'जापानी टाउन' कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहां बना देश का पहला जापानी इंडस्ट्रियल जोन है। इसे राजस्थान सरकार की एजेंसी RIICO और जापान की व्यापार संस्था JETRO ने मिलकर विकसित किया। इसका मकसद जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और कारोबार के लिए बेहतर माहौल देना था। करीब 1,160 एकड़ में फैले इस औद्योगिक क्षेत्र में आज 50 से ज्यादा जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। यहां ऑटोमोबाइल,इलेक्ट्रॉनिक्स,एयर कंडीशनर, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कई बड़ी कंपनियों के प्लांट हैं। इन कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया है और 26 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। नीमराना की पहचान सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। यहां रहने वाले जापानी लोगों के लिए जापानी रेस्तरां,होटल, सुपरमार्केट और दूसरी सुविधाएं भी हैं।

पीएम मोदी बोले...जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची मेरी छोटी बहन और दूरदर्शी

पीएम मोदी और जापान की पीएम ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जापान की पीएम सनाए तकाइची को अपनी छोटी बहन बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरी छोटी बहन, प्रधानमंत्री सनाए तकाइची, दोनों प्रतिनिधिमंडलों के सम्मानित सदस्य, मीडिया के सदस्य,नमस्कार और कोनिचिवा (इसका मतलब जापानी भाषा में हैलो होता है)। पीएम मोदी ने कहा कि भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पीएम तकाइची की भारत की पहली यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही एक दूरदर्शी और व्यापक रूप से सम्मानित नेता भी हैं। वे नारा प्रांत से आती हैं, जो भारत और जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक प्रमुख केंद्र है।

ताकाइची बोलीं...मोदी मेरे बड़े भाई जैसे

ताकाइची ने संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी 'सुंदर छोटी बहन' कहा। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते को भाई-बहन की तरह आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक नीति और भारत की महासागर पहल एक-दूसरे की पूरक हैं। इसी वजह से दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने को प्राथमिकता देने का फैसला किया है, ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे।

मोदी बोले...ऑटो सेक्टर जैसी साझेदारी अब एविएशन में भी होगी

मोदी ने कहा कि भारत और जापान ऑटोमोबाइल सेक्टर की सफलता को अब जहाज निर्माण, एविएशन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश टैलेंट मोबिलिटी,स्किल डेवलपमेंट,टेक्निकल इंटर्नशिप, रिसर्च,शिक्षा और स्टार्टअप में सहयोग बढ़ाएंगे। मोदी ने बताया कि अगले साल भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होंगे। इस मौके पर संस्कृति,पर्यटन और क्रिएटिव इकोनॉमी में भी साझेदारी मजबूत की जाएगी।

व्हाट्सऐप का नया फीचर : अब बिना नंबर दिए कर सकेंगे चैट,सरकार की चेतावनी के बाद कंपनी ने दी सफाई

नई दिल्ली,02 जुलाई 2026। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लाने की तैयारी में है, जिसके तहत यूजर्स को अपना फोन नंबर साझा किए बिना दूसरों से बात करने की सुविधा मिलेगी। इस फीचर को यूजरनेम नाम दिया गया है। इसे लेकर उठ रही सुरक्षा चिंताओं के बीच व्हाट्सऐप ने गुरुवार को अपना पक्ष साफ किया है। कंपनी ने बताया कि यह फीचर गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। व्हाट्सऐप ने साफ किया है कि यह फीचर पूरी तरह से वैकल्पिक है। यानी किसी भी यूजर पर यूजरनेम बनाने का कोई दबाव नहीं होगा। अगर कोई यूजर अपना नाम नहीं रखना चाहता, तो उसे इसकी जरूरत नहीं है। यह सुविधा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो ग्रुप चैट या नए लोगों से बात करते समय अपना मोबाइल नंबर गुप्त रखना चाहते हैं। व्हाट्सऐप इस फीचर के साथ एक अतिरिक्त सुरक्षा परत भी ला रहा है,जिसे यूजरनेम की कहा गया है। यह एक गुप्त कोड की तरह होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको मैसेज भेजना चाहता है,तो उसे आपका यूजरनेम और यह गुप्त कोड, दोनों की जानकारी होनी चाहिए। इससे अनजान लोगों द्वारा मैसेज भेजने की समस्या पर रोक लग सकेगी। यूजर अपनी सुविधा के अनुसार इस कोड को कभी भी बदल सकेंगे।

पीएफ नियमों में बड़ा बदलाव...अब मर्जी से कटेगा ज्यादा पैसा, एडवांस निकालना भी हुआ आसान,नए लेबर कोड के हिसाब से बदले नियम

नई दिल्ली,02 जुलाई 2026। नौकरीपेशा लोगों के भविष्य निधि यानी पीएफ से जुड़े नियमों में सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने साफ किया है कि अब तय कानूनी वेतन सीमा जो कि 15000 रुपए महीना है, उस पर 12 फीसदी का पीएफ काटना ही अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि भले ही आपकी मूल सैलरी 1 लाख रुपए महीना क्यों न हो, आपके पीएफ खाते में जरूरी योगदान के रूप में केवल 1800 रुपए ही काटे जाएंगे। इतनी ही रकम आपकी कंपनी भी अपनी तरफ से आपके खाते में डालेगी। हालांकि अगर कोई कर्मचारी चाहे तो अपनी मर्जी से इससे ज्यादा पैसा पीएफ में कटवा सकता है। मार्केटिंगनए नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी तय सीमा से ज्यादा पीएफ कटवाना चाहता है,तो यह पूरी तरह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। इसके लिए कंपनी को बराबर की ज्यादा रकम डालने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कंपनी चाहे तो ज्यादा पैसा दे सकती है और चाहे तो केवल तय रकम ही देगी। इसके अलावा कर्मचारी और कंपनी दोनों जब चाहें इस अतिरिक्त पैसे को कम या पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। इस बदलाव से अब कंपनियों को कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर बदलने में आसानी होगी। कर्मचारियों को जरूरत के समय पीएफ का पैसा निकालने में कोई परेशानी न हो,इसके लिए ईपीएफओ ने नियमों को बहुत सरल कर दिया है।

बेंगलुरु में पत्थर खदान में चट्टान गिरी,7 की मौत

हादसे के समय 17 लोग काम कर रहे थे,दिहाड़ी मजदूर थे सभी मृतक

बेंगलुरु,02 जुलाई 2026। कर्नाटक के बेंगलुरु में गुरुवार सुबह पत्थर खदान ढहने से 7 प्रवासी मजूदरों की मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी थी कि सभी मृतक बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन,बाद में स्पष्ट किया गया कि 5 मजदूर मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ और एक कर्नाटक के यादगीर का रहने वाला था। घटना के दौरान 17 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक,साउथ तालुक इलाके में मौजूद कावेरी क्रशर कंपनी की खदान में खनन चल रहा था। इसी दौरान 40 फीट ऊंचाई से चट्टान का बड़ा टुकड़ा मजदूरों पर आ गिरा। हादसे में 5 मजदूर भी घायल हो गए। पांचों खतरे से बाहर हैं। सभी मृतक व घायल दिहाड़ी मजदूर थे और वहां स्टोन क्रशर साइट पर काम कर रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शी बोला...पहाड़ी का हिस्सा कुछ ही सेकंड में ढह गया

एक्सकेवेटर चला रहे परशुराम ने बताया कि काम शुरू करने के लिए जैसे ही मैं मौके पर

पहुंचे और मशीन चालू की,तभी पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता,लेकिन उस समय नीचे करीब 18 लोग काम कर रहे थे। हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मलबे में दबे 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।

मृतकों के परिवार को 10-10 लाख की सहायता राशि

खदान मालिक ने मुआवजा देने पर सहमति जताई है। खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारी रंगप्पा ने बताया कि उन्होंने खदान मालिक से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को पांच-पांच लाख रुपये देने के लिए कहा, जिस पर उसने सहमति दे दी है।

खनन गतिविधियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे : सीएम

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि राज्य में खनन गतिविधियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार हादसा ब्लास्टिंग से नहीं, बल्कि मिट्टी के खिसकने के कारण हुआ है। विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर चलेगा बुलडोजर! पत्नी को थमाया गया नोटिस...

अयोध्या,02 जुलाई 2026। श्रीराम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आरोपी लवकुश मिश्रा के घर बुलडोजर चलने वाला है। एडीए ने लवकुश की पत्नी को इस संबंध में नोटिस थमा दिया है। सोहावल के बनवीरपुर में लवकुश मिश्रा का मकान बन रहा है। लवकुश ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर ये जमीन लेकर रखी थी। बता दें कि श्रीराम मंदिर मामले को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 'मुझे नहीं पता, हम तो इंतजार में हैं कि FIR कब होगा और FIR के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा? बुलडोज़र चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब

कुछ कर दिया। अब आस्था की बुनियाद पर क्या ये भी बर्दाश्त किया जाएगा? अब ये सरकार को तय करना है।' ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? यदि एफआईआर होगी तो पहले गोली चलेगी पैर पर या बुलडोजर चलेगा घर पर? क्योंकि ये तो सिर्फ मुस्लिम समाज पर चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए रोड पर नमाज नहीं पढ़ना, कोई मजहबी यात्रा होती है तो दुकानें बंद कर देना।

35 करोड़ का ऑफर और 15 विधायकों का इस्तीफा...विजय की सरकार गिराने की साजिश का खुला राज

नई दिल्ली,02 जुलाई 2026। तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है,जहां अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व वाले टीवीके विधायक ने दावा किया है कि उन्हें सदन अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्तावित विधानसभा प्रस्ताव पर अपना वोट प्रभावित करने के लिए 35 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। दरअसल,टीवीके विधायक एन. इलैयाराजा की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार डीएमके नेता सेंथिल बालाजी और उनके भाई वी अशोक कुमार से जुड़े बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया कि इस साजिश में टीवीके के 15 विधायकों के एक साथ इस्तीफे की साजिश रचकर सरकार को गिराने की योजना शामिल थी। टीवीके विधायक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने जांच शुरू की और एक कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। जांच

के दौरान,अधिकारियों को डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी से संबंध होने की खबर मिली। इसके बाद दो और लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। एन. इलायाराजा द्वारा चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि आईपीडीएस नामक परामर्श फर्म के एक व्यक्ति ने उन्हें तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर (जो टीवीके नेता हैं) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 35 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। 29 जून को विधायक इलैयाराजा द्वारा चेन्नई पुलिस आयुक्त के पास दर्ज कराई गई।

बिहार-एमपी और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान 30 जुलाई को वोटिंग

नई दिल्ली,02 जुलाई 2026। निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई 2026 को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त 2026 को नतीजों की घोषणा होगी। जिन-जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव के तारीखों का एलान किया है, उनमें बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट शामिल है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, इस उपचुनाव की प्रक्रिया आगामी 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन यानी पर्चा दाखिल कर सकेंगे।

देश दहलाने की साजिश नाकाम! आईएसआई से जुड़े चार आतंकी गिरफ्तार,पुलिस चौकियों और धार्मिक स्थलों की कर रहे थे रेकी

नई दिल्ली,02 जुलाई 2026। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर चल रहे एक बड़े आतंकी और अवैध हथियार नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने चार खतरनाक आरोपियों को दबोचा है,जो दिल्ली के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

पंजाब से दिल्ली तक फैला नेटवर्क

मिली जानकारी के मुताबिक,इस आतंकी नेटवर्क के तार सीधे सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। पुलिस ने जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से तीन पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी दिल्ली का ही है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम: शुभदीप सिंह,गुरजंट सिंह, साजन सिंह और गगनप्रीत। ये सभी आरोपी पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर शाहजाद भट्टी और उसके गुर्गों के सीधे संपर्क में थे। अपनी पहचान छिपाने और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजरोंसे बचने के लिए ये आरोपी विदेशी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे,जो इन्हें पाकिस्तान से मुहैया कराए गए थे।

पुलिस थानों और धार्मिक स्थलों की हो चुकी थी रेकी

गौरतलब है कि इस पूरे नेटवर्क में दिल्ली से पकड़ा गया आरोपी गगनप्रीत सबसे खतरनाक भूमिका में था। उसे पाकिस्तानी आकाओं ने बेहद संवेदनशील काम सौंपे थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक,गगनप्रीत दिल्ली के बड़े पुलिस प्रतिष्ठानों,थानों,पुलिस पिकेट और प्रमुख धार्मिक स्थलों की रेकी कर चुका था। उसने कई जगहों के वीडियो बनाकर पाकिस्तान भी भेजे थे। उसे दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी (लोन वोल्फ अटैक) करने का भी निर्देश मिला था।

पुलिस ने ऐसे दबोचा

स्पेशल सेल को काफी दिनों से इनपुट मिल रहे थे कि आईएसआई पंजाब के युवाओं को बरगलाकर दिल्ली-एनसीआर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रही है। इसके बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। सबसे पहले पंजाब के अमृतसर से शुभदीप सिंह को उठाया गया।

संपादकीय

मंच की कुर्सी,प्रोटोकॉल और लोकतंत्र की मर्यादा

शासकीय आयोजनों में दिखावे की संस्कृति पर विराम लगाने की जरूरत...

लोकतंत्र में पद का सम्मान जरूरी है,लेकिन पद से भी ऊपर जनता का सम्मान होता है। शासकीय कार्यक्रम जनता के लिए होते हैं और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शासन की योजनाओं, जनहित के कार्यों और सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में यदि किसी कार्यक्रम में चर्चा का केंद्र बच्चों,जनता या योजनाओं के बजाय मंच की व्यवस्था और बैठने की जगह बन जाए तो यह व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

हाल ही में राजपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में मंच व्यवस्था को लेकर सामरी विधायक के नाराज होने का मामला सामने आया। शाला प्रवेश उत्सव जैसे आयोजन शिक्षा के उत्साह,बच्चों के स्वागत और नए सत्र की शुरुआत के लिए होते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में सबसे बड़ा सम्मान उन बच्चों का होना चाहिए,जिनके भविष्य को लेकर पूरा आयोजन किया जाता है। लेकिन जब मंच व्यवस्था को लेकर विवाद की स्थिति बनती है तो यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे शासकीय आयोजनों में प्रोटोकॉल को लेकर स्पष्टता और संतुलन की कमी है।

यह केवल किसी एक व्यक्ति या एक कार्यक्रम का विषय नहीं है। यह एक व्यापक व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है कि आखिर शासकीय मंचों पर किसे प्राथमिकता मिले और उसका आधार क्या हो?

लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। विधायक,सांसद,पंचायत प्रतिनिधि और नगरीय निकायों के चुने हुए सदस्य सीधे जनता के वोट से चुनकर आते हैं। वे जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को शासन तक पहुंचाने वाले प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए शासकीय कार्यक्रमों में उनका सम्मान और उचित स्थान लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है।

लेकिन इसके साथ यह भी उतना ही आवश्यक है कि मंच व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा या प्रभाव के आधार पर नहीं,बल्कि निर्धारित नियमों और प्रोटोकॉल के आधार पर हो। नामांकित सदस्य,मनोनीत पदाधिकारी, निगम-मंडल-आयोगों के गैर-निर्वाचित अध्यक्ष या अन्य जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए,लेकिन उनकी भूमिका और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका में अंतर को स्पष्ट रूप से समझना होगा।

सरकार और प्रशासन को इस दिशा में एक समान और पारदर्शी प्रोटोकॉल बनाने की आवश्यकता है। हर विभाग,हर जिले और हर कार्यक्रम में एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए,ताकि किसी को कम या ज्यादा महत्व मिलने की भावना पैदा न हो। नियम स्पष्ट होंगे तो विवादों की संभावना भी कम होगी।

आज सबसे बड़ी चुनौती केवल प्रोटोकॉल की नहीं,बल्कि बढ़ती हुई वीआईपी संस्कृति की है। लोकतंत्र में पद सेवा का माध्यम होना चाहिए, विशेष अधिकार जताने का नहीं। दुर्भाग्य से कई बार छोटे-बड़े आयोजनों में मंच,स्वागत,कुर्सी और सम्मान को लेकर ऐसी प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, जिससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है।

यह देश 150 करोड़ नागरिकों की साझी भागीदारी से चलता है। हर नागरिक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का बराबर का भागीदार है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि और शासकीय अधिकारी अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के कारण अलग भूमिका में होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में मूल भावना समानता की ही है।

लाल बत्ती हटाने या सरकारी सुविधाएं कम करने भर से वीआईपी संस्कृति समाप्त नहीं होगी। इसके लिए समाज और व्यवस्था दोनों को अपनी सोच बदलनी होगी। जमीनी स्तर पर खुद को विशेष दिखाने की प्रवृत्ति,हर जगह सम्मान की अपेक्षा और पद के आधार पर अलग व्यवहार की मांग लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है।

शासकीय कार्यक्रमों की गरिमा तभी बनी रहेगी जब वहां व्यक्ति से ज्यादा उद्देश्य को महत्व दिया जाएगा। शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रमों में सबसे बड़ा चेहरा बच्चा होना चाहिए,किसान सम्मेलन में किसान,स्वास्थ्य कार्यक्रम में मरीज और जनकल्याण कार्यक्रमों में आम नागरिक।

मंच की कुर्सियां बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती,लेकिन मंच की सोच बदलने से लोकतंत्र मजबूत होता है। जरूरत इस बात की है कि शासकीय कार्यक्रम सत्ता प्रदर्शन का माध्यम न बनकर जनसेवा और जनभागीदारी का प्रतीक बनें।क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी कुर्सी किसी नेता,अधिकारी या पदाधिकारी की नहीं,बल्कि जनता की होती है।

कानूनी नोटिस या दबाव की रणनीति?

खबरों पर सवाल उठाने वालों के लिए भी जरूरी है जवाबदेही

जब खबर छपती है...तो सवाल उठते हैं...जब सवालों पर नोटिस आता है...तो लोकतंत्र की असली परीक्षा शुरू होती है...

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

पत्रकारिता का मूल धर्म है – सवाल पूछना। सत्ता,व्यवस्था और संस्थानों से जवाब मांगना। लेकिन यही पत्रकारिता तब कटघरे में खड़ी हो जाती है जब सवालों के जवाब देने के बजाय खबर लिखने वाले को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। हाल ही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से जुड़ी खबरों को लेकर भेजे गए कानूनी नोटिस ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या हर आलोचनात्मक खबर को मानहानि मान लिया जाएगा या फिर सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की मांग करना लोकतांत्रिक अधिकार है?

कानूनी नोटिस में भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 356 के तहत मानहानि का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि प्रकाशित खबरों से संबंधित अधिकारियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति,पदोन्नति और सेवा नियमों से जुड़े मामलों को प्रशासनिक या न्यायिक माध्यम से उठाया जाना चाहिए था,मीडिया के माध्यम से नहीं।

यह तर्क अपने स्थान पर है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। पत्रकारिता का उद्देश्य किसी व्यक्ति को बदनाम करना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर व्यवस्था से सवाल करना है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सरकारी पदों पर नियुक्ति,पदोन्नति,नियमों की व्याख्या और विभागीय निर्णय जैसे विषय सार्वजनिक हित से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में मीडिया की भूमिका केवल सूचना देना नहीं,बल्कि जनता के सामने तथ्यों को रखना भी होती है।

सवाल यह है कि यदि किसी विभागीय प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो उसका समाधान क्या केवल कानूनी नोटिस होगा? या फिर संबंधित विभाग को सामने आकर दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? लोकतंत्र में जवाबदेही केवल पत्रकारों की नहीं होती, बल्कि उन संस्थानों की भी होती है जिनके निर्णय जनता के विश्वास से जुड़े होते हैं।

किसी भी खबर पर आपत्ति हो सकती है। तथ्य गलत हों तो उसका खंडन किया जा सकता है। कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है। लेकिन खबर के बाद सीधे 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग,माफी और प्रकाशन रोकने जैसी शर्तें यह सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि क्या यह केवल कानूनी अधिकार का प्रयोग है या फिर आलोचनात्मक पत्रकारिता पर दबाव बनाने का प्रयास?

आज के दौर में पत्रकारिता भी चुनौतियों से घिरी है। एक ओर फर्जी खबरों और बिना प्रमाण के आरोपों पर नियंत्रण जरूरी है,वहीं दूसरी ओर सच बोलने और सवाल उठाने वाली पत्रकारिता को भी संरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि यदि हर सवाल के जवाब में नोटिस और मुकदमे का डर खड़ा कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका कमजोर होगी।

वहीं पत्रकारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। किसी भी व्यक्ति की छवि प्रभावित करने वाली खबर प्रकाशित करने से पहले दस्तावेज, पक्ष और तथ्यात्मक आधार मजबूत होना चाहिए। आरोप और प्रमाण के बीच की दूरी को खत्म करना ही निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान है।

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पहलू यही है कि विवाद किसी व्यक्ति विशेष का नहीं,बल्कि व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का है। यदि नियुक्तियां नियमों के अनुसार हुई हैं तो दस्तावेज खुद सबसे बड़ा जवाब हैं। और यदि कहीं अनियमितता है तो उसे छिपाने के बजाय जांच और सुधार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

कानूनी नोटिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अधिकार है,लेकिन सवाल पूछना भी लोकतंत्र का अधिकार है। जरूरत इस बात की है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझें। क्योंकि मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां व्यवस्था सवालों से डरती नहीं और पत्रकारिता तथ्यों से आगे बढ़कर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का माध्यम नहीं बनती। अंततः यही कहा जा सकता है कि खबरों से असहमति हो सकती है...लेकिन सवालों को दबाने की कोशिश लोकतंत्र के लिए हमेशा चिंता का विषय रहती है।

डिजिटल प्राइवेसी की नई परत,लेकिन भीतर छिपे बड़े खतरे

मेटा का जाल,सरकार का शिकंजा : यूजरनेम की आग में जल रहा भरोसा...

डिजिटल पहचान का सबसे बड़ा बदलाव: सुविधा या राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट?

प्रो.आर.के.जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

मोबाइल नंबर अब तक डिजिटल पहचान का सबसे भरोसेमंद आधार रहा है,लेकिन अब उसकी जगह यूजरनेम लेने की तैयारी है। बदलाव जितना आधुनिक दिखता है,जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। व्हाट्सऐप यूजरनेम सुविधा ला रहा है,जिससे उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर छिपाकर यूजरनेम के माध्यम से नए संपर्कों से बातचीत कर सकेंगे। दावा है कि इससे निजता मजबूत होगी,लेकिन भारत सरकार ने इसके संभावित खतरों को समय रहते भांप लिया। मेटा को नोटिस भेजकर इस फीचर के भारत में रोलआउट पर अस्थायी रोक लगाना महज तकनीकी कदम नहीं, बल्कि भारत के 50 करोड़ से अधिक व्हाट्सऐप यूजर्स की डिजिटल सुरक्षा का सवाल है। जिस देश में रोज हजारों साइबर ठगी होती हों, वहां पहचान को नंबर से हटाकर केवल यूजरनेम के भरोसे छोड़ना क्या अपराधियों को नया हथियार नहीं देगा? आखिर डिजिटल दुनिया में प्राथमिकता सुविधा को मिले या सुरक्षा को?

पहली नजर में मेटा का यह प्रस्ताव बेहद आकर्षक लगता है। इसके तहत हर उपयोगकर्ता 3 से 35 कैरेक्टर्स (अक्षर, संख्या, पीरियड और अंडरस्कोर) वाला यूनिक यूज़रनेम चुन सकेगा। इसके बाद बातचीत के लिए मोबाइल नंबर साझा करने की जरूरत नहीं होगी। नंबर केवल अकाउंट वेरिफिकेशन तक सीमित रहेगा,जबकि चैट में उसकी जगह यूजरनेम दिखाई देगा। कंपनी का दावा है कि यूजरनेम की जैसी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था अनचाहे संदेशों और संदिग्ध संपर्कों पर प्रभावी नियंत्रण रखेगी। कागज पर यह व्यवस्था निजता को मजबूत करती दिखाई देती है,लेकिन तकनीक का इतिहास बताता है कि हर नई सुविधा अपने साथ नए जोखिम भी लाती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि यह फीचर कितना आकर्षक है, बल्कि यह है कि इसकी सुरक्षा कितनी अभेद्य और भरोसेमंद है।

भारत की चिंता वाजिब है। यहां साइबर अपराध पहले ही महामारी बन चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट,फर्जी बैंक अलर्ट,निवेश घोटाले,ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया इमपर्सनेशन और भावनात्मक ठगी लाखों लोगों को शिकार बना चुके हैं। ऐसे में यदि कोई ठग किसी अधिकारी,पत्रकार,उद्योगपति,लोकप्रिय हस्ती या आम नागरिक के नाम जैसा यूजरनेम पहले ही ले ले (यूजरनेम स्क्वाटिंग),तो छद्मवेश (इमपर्सनेशन) और पहचान की चोरी आसान हो जाएगी। इसके जरिए फर्जी प्रोफाइल बनाकर पैसे ऐंठना,संवेदनशील जानकारी हासिल करना,अफवाह फैलाना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना आसान होगा। तब यह केवल व्यक्ति का नहीं,बल्कि जनविश्वास, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का संकट बन जाएगा। इसलिए सरकार की आशंका कल्पना नहीं, डिजिटल हकीकत है।

इन्हीं आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने मेटा से तीन दिनों में विस्तृत जवाब मांगा है। कंपनी को फीचर का डिजाइन, प्राइवेसी प्रोटोकॉल,सुरक्षा तंत्र,पहचान सत्यापन और दुरुपयोग रोकने के उपाय स्पष्ट करने होंगे। साथ ही समीक्षा पूरी होने तक भारत में इसका रोलआउट रोकने को कहा गया है। यह फैसला तकनीकी प्रगति का विरोध नहीं,बल्कि जिम्मेदार डिजिटल शासन का संकेत है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,साइबर सुरक्षा नीतियों और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों का भारतीय कानूनों और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। डिजिटल भारत में किसी वैश्विक कंपनी की सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण नागरिकों की सुरक्षा है।

फिर भी इस प्रस्ताव के सकारात्मक पक्षों को नकारा नहीं जा सकता। आज सेवाओं,व्यापार,फ्रीलांसिंग,ऑनलाइन शिक्षा,कंटेंट क्रिएशन और व्यावसायिक संपर्क के लिए मोबाइल नंबर साझा करना लगभग अनिवार्य हो गया है। इसका नतीजा अनचाहे कॉल,स्पैम संदेश,डेटा लीक और निजी जानकारी के दुरुपयोग के रूप में सामने आता है। यदि नए संपर्कों से केवल यूजरनेम से संवाद हो,तो मोबाइल नंबर काफी हद तक छिपा रह सकता है। इसलिए अनेक उपयोगकर्ता इस सुविधा का स्वागत कर रहे हैं,क्योंकि इससे गोपनीयता मजबूत होगी और डिजिटल ट्रैकिंग घटेगी। लेकिन अच्छी मंशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होती,मजबूत सुरक्षा के बिना सबसे उपयोगी तकनीक भी सबसे खतरनाक दरवाजा बन सकती है।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता यही है। उनके अनुसार यह फीचर यूजरनेम स्क्वाटिंग,फर्जी खातों और सोशल इंजीनियरिंग हमलों को बढ़ावा दे सकता है। भारत जैसे देश में, जहां भाषाई विविधता,अलग-अलग लिपियां,समान नामों की भरमार और ग्रामीण-शहरी डिजिटल अंतर है,वहां पहचान का सत्यापन अधिक जटिल है। यदि मेटा ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त स्थानीय परीक्षण नहीं किए,तो जोखिम कई गुना बढ़ सकते हैं। केवल एल्गोरिद्म पर्याप्त नहीं;स्थानीय भाषाओं की समझ,प्रभावी शिकायत निवारण, त्वरित सत्यापन और संदिग्ध खातों पर फौरन कार्रवाई भी अनिवार्य होगी।

प्लास्टिक सुविधा है,लेकिन अमूल्य जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं...

डॉ. प्रितम भि.गेडाम

प्रकृति और समस्त जीव-जगत एक-दूसरे के पूरक हैं। मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता, शोध और तकनीकी विकास के बल पर जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया। इन आविष्कारों ने जीवन को आसान तो बनाया,लेकिन बढ़ती भौतिक इच्छाओं और स्वार्थ ने मानव को प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करने के लिए भी प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप जिन साधनों को सुविधा का माध्यम समझा गया था,वही आज मानव और पर्यावरण के लिए गंभीर संकट बन चुके हैं। प्लास्टिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। आज स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि हमें मरने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं रह गई हैं। हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण,मिलावट, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और प्लास्टिक का अनियंत्रित उपयोग ही अनेक गंभीर बीमारियों द्वारा अकाल मृत्यु दे रहा हैं। प्लास्टिक ने केवल पर्यावरण को ही नहीं,बल्कि मानव स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित किया हैं। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह प्राकृतिक रूप से बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होता। एक बार उपयोग के बाद यह सैकड़ों नहीं बल्कि लगभग हजार वर्षों तक पर्यावरण में बना रह सकता हैं। समय के साथ यह टूटकर माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक में बदल जाता है, जो मिट्टी, जल और वायु के माध्यम से पूरी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में मानव के मस्तिष्क,रक्त,फेफड़ों, गर्भस्थ शिशु तथा विभिन्न जीवों के शरीर में भी प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मिलने की पुष्टि हुई हैं। यह स्थिति भविष्य के लिए अत्यंत गंभीर चेतावनी हैं। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन प्लास्टिक के सूक्ष्म कण भोजन और पानी के साथ शरीर में पहुँचा रहे हैं। प्लास्टिक का कचरा पचाया नहीं जा सकता। पशु-पक्षी अक्सर प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य प्लास्टिक सामग्री निगल लेते हैं,जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती हैं। नदियाँ,समुद्र और जंगल भी प्लास्टिक प्रदूषण से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। प्लास्टिक जलाने पर निकलने वाली विषैली गैसें वायु प्रदूषण बढ़ाती है,जबकि भूमि में पड़े प्लास्टिक से निकलने वाली गैसें जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के लिए खतरा बनती हैं।

प्लास्टिक में मौजूद रासायनिक तत्व हार्मोन असंतुलन,प्रजनन संबंधी समस्याएँ,हृदय रोग, थायरॉइड विकार,मधुमेह,श्वसन रोग तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ाते हैं। प्लास्टिक उद्योग में कार्य करने वाले लोगों में फेफड़ों की बीमारियों की संभावना भी अधिक पाई गई हैं। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं,बल्कि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका हैं। प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता हैं। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित करना हैं। यह केवल एक प्रतीकात्मक दिवस नहीं,बल्कि पृथ्वी,पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का वैश्विक अभियान हैं। यदि आज प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता कम नहीं हुई,तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं।

भारत में हर वर्ष लगभग 5.5 मिलियन टन सिंगल-यूज़ प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता हैं। औसतन एक भारतीय नागरिक वर्षभर में लगभग 11 किलोग्राम प्लास्टिक का उपयोग करता है, जिसमें कैरी बैग,पैकेजिंग सामग्री तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएँ शामिल हैं। इनमें से लगभग 4 किलोग्राम केवल सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का होता हैं। देश में उत्पन्न होने वाले लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे में 43 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का हैं। चिंताजनक बात यह है कि लगभग 19 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा एकत्र ही नहीं हो पाता और वह खुले वातावरण में फैलकर मिट्टी,जलस्रोतों और जीव-जंतुओं को नुकसान पहुँचाता हैं। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिंगल-यूज़ प्लास्टिक कचरा उत्पादक देश हैं। यद्यपि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कई नियम लागू किए गए हैं,फिर भी अनेक स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग आज भी जारी हैं। महाराष्ट्र दक्षिण एशिया में सर्वाधिक म्युनिसिपल ठोस कचरा उत्पन्न करने वाला राज्य बन चुका हैं। वहीं,समुद्री तटों और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध केरल में भी प्रतिवर्ष 1,30,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है,जिसमें से केवल लगभग 3 प्रतिशत का ही पुनर्चक्रण हो पाता हैं।

हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है पर्यावरण के प्रति बढ़ती लापरवाही और बेफिक्री। बहुत कम लोग किसी विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते है, जबकि अधिकांश लोग बिना सोचे-समझे दूसरों का अनुसरण करते रहते हैं। जब व्यक्तिगत सुविधा को सामाजिक और पर्यावरणीय हित से अधिक महत्व दिया जाता है, तब उसके दुष्परिणाम पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ते है, प्लास्टिक प्रदूषण इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। आज भी प्रतिबंध लागू होने के बावजूद बाजारों में प्लास्टिक की थैलियों का खुलेआम उपयोग किया जा रहा हैं। कई बार दुकानदार मना करते हैं, फिर भी ग्राहक स्वयं प्लास्टिक बैग की मांग करते हैं। यही स्थिति अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की भी हैं। यह केवल नियमों की अनदेखी नहीं,बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के प्रति हमारी गैर-जिम्मेदार सोच को भी दर्शाती हैं। इसी प्रकार सड़क किनारे कचरा फेंकने की आदत भी धीरे-धीरे बड़े कूड़े के ढेर में बदल जाती हैं। जब किसी को ऐसा करने से रोका जाता है, तो कई बार विवाद की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती हैं।

पहले गंभीर बीमारियाँ मुख्यतः नशे या गलत जीवनशैली के कारण होती थीं,लेकिन अब प्रदूषण और पर्यावरणीय लापरवाही के कारण छोटे बच्चे,स्वस्थ व्यक्ति और नशामुक्त लोग भी गंभीर रोगों का शिकार बन रहे हैं। दुधारू पशु प्लास्टिक की थैलियाँ निगल लेते हैं,समुद्री जीव प्लास्टिक कचरे में फँस जाते हैं और पक्षी भी प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं। इसके बाद इन्हीं पशुओं का दूध,मांस या अन्य उत्पाद मानव के भोजन का हिस्सा बनते है, जिससे प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। आज बाजार में लगभग हर प्रकार के प्लास्टिक के बर्तन उपलब्ध हैं। विशेष रूप से गर्म भोजन और गर्म पेय पदार्थों के लिए प्लास्टिक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है,क्योंकि प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक रसायन भोजन में मिल सकते हैं। यही कारण है कि कैंसर सहित अनेक गंभीर रोगों के मामलों में लगातार वृद्धि चिंता का विषय बनती जा रही है,आज देश में हर गली-मोहल्ले, रिश्तेदारों,पहचान में कैंसर के रोगी देखने मिल रहे हैं। यदि हमें अपने देश,समाज और पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है, तो परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं,बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य हैं। कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना,एकल-उपयोग प्लास्टिक से बचना, कचरे का सही निपटान करना और पर्यावरण संबंधी कानूनों का पालन करना हमारी दैनिक आदत का हिस्सा बनना चाहिए। प्रकृति हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन निःशुल्क प्रदान करती हैं। इसलिए उनका संरक्षण करना भी हमारा दायित्व हैं। यदि आज हम जागरूक नहीं हुए,तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। प्लास्टिक केवल सुविधा का साधन है, लेकिन मानव जीवन और पर्यावरण उससे कहीं अधिक मूल्यवान हैं। जीवन एक बार मिलता है,मोल समझें। प्रदूषण द्वारा अपने साथ दूसरों की भी जिंदगी के लिए खतरा पैदा करना अनुचित है, संगीन अपराध हैं। इसलिए आइए,अंतराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम करेंगे,पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाएँगे और एक स्वच्छ, स्वस्थ तथा सुरक्षित भविष्य के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएँगे।

करले तियारी ग संगवारी मोर

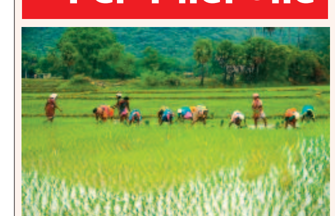

अशोक पटेल आशु
तुस्मा, शिवरीनारायण
छत्तीसगढ़

करले तियारी ग संगवारी मोर
दिन आगे खेती-किसानी के
बरसत हे बादर ग संगवारी मोर
झकर झड़ी हे ग बिहानी के।
करले तियारी....

रुखराई हर जम्मों हरियागे
परिया-झरिया के भाग जागे।
बखरी-बारी जम्मों ह रुंधागे
खेती-किसानी के दिन आगे।
बइला नांगर ला संगवारी मोर
दिन आगे हे अब धान बोनी के
करले तियारी....

रोपा धानी हर लहरावय
धनहा माटी हर महमहावय।
इही माटी सोना उपजावय
धरती के बड़ महिमा हावय।
धरती के सेवा कर संगवारी रे
कोरा हर छलके पानी-पानी रे
करले तियारी....

मेड़-पार खनागे,खेत ह जोतागे
बन-कचरा खनागे,काँटा ह कटागे।
गोबर-खातु जम्मों ह पलागे
डभरा ह पटागे,डिपरा ह खनागे।
नांगर ल धरले ग संगवारी मोर
दिन आगे अब खेती-किसानी के
करले तियारी....

> सपने वो नहीं जो हम सोते हुये देखते हैं, सपने वो हैं जो हमे सोने नहीं देते ।
>
> डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

सत्ता से जुड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं?' कांग्रेस का पुलिस-प्रशासन पर बड़ा हमला

वायरल ऑडियो...सीतापुर विधायक विवाद और भिट्ठीकला जमीन घोटाले में लीपापोती का आरोप...6 जुलाई को आईजी कार्यालय तक निकलेगी 'न्याय यात्रा'

एसआईटी जांच की मांग दोहराई...कहा...कानून का डंडा सिर्फ आम आदमी पर नहीं, प्रभावशाली लोगों पर भी समान रूप से चलना चाहिए...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026

(घटती-घटना)। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने जिले के तीन चर्चित मामलों को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा किया हैं। गुरुवार को राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिन मामलों में सत्तारूढ़ दल के नेताओं अथवा उनके प्रभावशाली समर्थकों के नाम सामने आए हैं,उनमें पुलिस की कार्रवाई या तो बेहद धीमी है या फिर जांच को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है। कांग्रेस ने इसे कानून के समान अनुपालन के सिद्धांत के विपरीत बताते हुए तीनों मामलों की एसआईटी से जांच कराने की मांग दोहराई।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि यदि आम नागरिक के खिलाफ तत्काल अपराध दर्ज हो सकता है तो सत्ता से जुड़े लोगों के मामलों में अलग मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि इन मामलों में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर 6 जुलाई को राजीव भवन से पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कार्यालय तक न्याय यात्रा निकाली जाएगी और ज्ञापन सौंपा जाएगा।

पहला मामला : वायरल ऑडियो पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल...

कांग्रेस ने सबसे पहले हाल में सामने आए कथित वायरल टेलीफोनिक ऑडियो का मुद्दा उठाया। पार्टी का कहना है कि 18-19 जून के बीच वायरल हुए इस ऑडियो में कलाकेन्द्र मैदान के आबंटन के बदले लाखों रुपये के लेन-देन की चर्चा है। कांग्रेस का दावा है कि बातचीत में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और महापौर मंजूषा भगत की आवाज होने की बात कही जा रही है।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 22 जून को महापौर ने स्वयं संबंधित ऑडियो को एआई से तैयार किया गया बताते हुए आजाक थाने में लिखित शिकायत दी थी। इसके बावजूद अब तक न अपराध दर्ज हुआ और न ही प्रभावी जांच शुरू हुई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब शहर की प्रथम नागरिक की शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हो रही,तो इससे पुलिस की कार्यशैली पर संदेह पैदा होता है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस मामले में संबंधित पक्षों को अपने कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।

कांग्रेस ने गिनाई अपनी पहल...

कांग्रेस ने बताया कि 22 जून को कलेक्टर को ज्ञापन देकर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। इसके बाद 27 जून को नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आजाक थाना पहुंचा, जहां जानकारी मिली कि मामला उनके क्षेत्राधिकार का नहीं है और कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है। इसके बाद 28 जून को पुलिस अधीक्षक से मिलकर तीन दिनों के भीतर एसआईटी गठित करने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ।

दूसरा मामला : सीतापुर विधायक और नायब तहसीलदार विवाद

कांग्रेस ने 27 मई को सीतापुर में विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच हुए विवाद का भी उल्लेख किया। कांग्रेस का आरोप है कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी स्वयं एसडीएम थे और पूरे प्रदेश के राजस्व कर्मचारी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे,लेकिन गंभीर धाराएं लगने के बावजूद आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई।

कांग्रेस ने कहा कि उसने 3 जून को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। पार्टी का आरोप है कि सत्ता के दबाव में कार्रवाई लंबित रखी गई।

तीसरा मामला: भिट्ठीकला जमीन घोटाला

प्रेसवार्ता में कांग्रेस ने भिट्ठीकला की एक विधवा महिला की जमीन के कथित फर्जीवाड़े का मामला भी प्रमुखता से उठाया। पार्टी का आरोप है कि 24 डिसमिल भूमि की खरीद के नाम पर कूटरचना कर पूरी 3.14 एकड़ जमीन हड़प ली गई। कांग्रेस के अनुसार कलेक्टर ने तहसीलदार को संबंधित लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कांग्रेस का दावा है कि मामले में प्रभावशाली लोगों की निकटता के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है। पार्टी ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव भी पीड़ित महिला से मिल चुके हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर चुके हैं।

न्याय यात्रा की घोषणा

कांग्रेस ने घोषणा की कि 6 जुलाई को राजीव भवन से आईजी कार्यालय तक न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। यात्रा के समापन पर पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर वायरल ऑडियो, सीतापुर विधायक विवाद और भिट्ठीकला जमीन मामले में एसआईटी गठित कर समयबद्ध एवं निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। अंत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा,जब सत्ता से जुड़े लोगों के मामलों में पुलिस निष्क्रिय दिखाई देती है और आम नागरिकों पर तत्काल कार्रवाई होती है,तब कानून के समान अनुपालन पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जबकि नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा,यदि प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तो जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास कमजोर होगा। कानून सबके लिए समान होना चाहिए।

बारिश के बीच गाज गिरने से खरसिया रोड में धू-धू कर जला ट्रक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर के खरसिया रोड में खड़ी एक ट्रक पर बिजली गिरने से उसमें भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार बुधवार को अंबिकापुर में आकाशीय बिजली खरसिया रोड में अन्य वाहनों के साथ खड़ी एक डंपर पर अचानक गिरी, और देखते ही देखते ट्रक के केबिन और इंजन में आग भड़क उठी। आग की लपटें देखते ही देखते 10-15 फीट ऊंची उठने लगी और काला धुआं आसमान में फैल गया। आसपास हड़कंप की स्थिति बन गई। पास में खड़े अन्य वाहन आग की चपेट में न आयें इसका प्रयास शुरू हुआ। वहीं सूचना मिलते ही होमगार्ड के अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन डंफर वाहन बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस घटना के सामने आने के बाद बारिश के दौरान खुले मैदान में वाहनों को खड़ा करना खतरनाक हो सकता है, इस पर वाहन स्वामियों को भी ध्यान देने की जरूरत है।

विशेष लोक अदालत के तहत अंबिकापुर को मिले 34 प्रकरण

सुप्रीम कोर्ट की पहल पर लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

विशेष लोक अदालत 2026 के तहत अंबिकापुर को कुल 34 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी सूचना के अनुसार, न्याय को सरल, सुलभ और घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह विशेष पहल शुरू की गई है। इसके तहत देशभर में लंबित उपयुक्त मामलों को सुलह-समझौते के जरिए निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल से की गई थी, जिसकी परिणति 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में होगी। अधिकारियों के अनुसार,अंबिकापुर जिले में प्राप्त 34 प्रकरणों को लेकर संबंधित पक्षों से संपर्क किया जा रहा है। इन मामलों में पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों को समाधान निकालने में मदद करेंगे। इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित, सरल और कम खर्च में निपटारा करना है। इसके माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी और आपसी सहमति से विवाद समाप्त किए जा सकेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित वादकारियों, अधिवक्ताओं और अन्य पक्षों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इच्छुक पक्षकार अपने मामलों को समाधान समारोह में शामिल कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट और निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लंबित मामलों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। अंबिकापुर में 34 मामलों का चयन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बाइक की ठोकर से घायल ग्रामीण की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बाइक की ठोकर से घायल ग्रामीण की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया मृतक दखल राजवाड़े पिता स्व. भवन राजवाड़े 48 वर्ष, बीते 28 जून को अपनी पत्नि जमालो, पुत्री कृष्णा के साथ रिश्तेदारी में ग्राम डुमरिया गया था। यहां आने के बाद बच्चों के लिये किराना दुकान में बिस्किट लेने गया, इसी दौरान पीछे से बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूरजपुर जिला अस्पताल से रिफर करने पर स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान गुरूवार को सुबह करीब 11.19 बजे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

कमजोर मानसून के बीच पहली तेज बारिश ने बढ़ाई चिंता, खेती से लेकर शहर की व्यवस्था तक पड़े असर

जून में सामान्य से 50 फीसदी कम वर्षा,जुलाई में मानसून ने पकड़ी रफ्तार,किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार,पहली मूसलाधार बारिश में जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में इस वर्ष मानसून की शुरुआत उम्मीद के अनुरूप नहीं रही। जून में मानसून तय समय पर पहुंचने के बावजूद उसकी सक्रियता कमजोर रही, जिसका असर पूरे संभाग में वर्षा के आंकड़ों पर साफ दिखाई दिया। सामान्य से करीब 50 प्रतिशत कम बारिश होने से किसानों की चिंता बढ़ गई थी। हालांकि जुलाई की शुरुआत के साथ मानसून ने रफ्तार पकड़ी है और पिछले दो दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश ने खेती-किसानी को गति देने के साथ ही शहर की व्यवस्थाओं की भी परीक्षा शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार जून में सरगुजा संभाग में केवल 109 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य औसत लगभग 200 मिमी है। यानी पूरे महीने में औसत से करीब आधी बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि मानसून समय पर पहुंचा था, लेकिन पर्याप्त सक्रिय नहीं होने के कारण अपेक्षित वर्षा नहीं हो सकी।

उन्होंने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह से मानसून फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को उत्तरी छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट के बीच अंबिकापुर में 29.6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। आने वाले दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अच्छी से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मानसून की सुस्त शुरुआत का सबसे अधिक असर खेती पर पड़ा। पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण कई किसानों ने धान की बोआई टाल दी थी। अब बारिश शुरू होने के बाद खेतों में गतिविधियां तेज हो गई हैं और संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में धान बोआई का कार्य शुरू हो चुका है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में लगातार अच्छी बारिश होती रही तो खेती सामान्य गति पकड़ लेगी। हालांकि मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य से कुछ कमजोर रहने की संभावना भी जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के दौरान बीच-बीच में इसकी सक्रियता कम हो सकती है,जिससे कुछ क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा की स्थिति बन सकती है। ऐसे में किसानों को मौसम के बदलते मिजाज पर लगातार नजर रखनी होगी।

शहर की जल निकासी व्यवस्था चौपट : गुरुवार दोपहर करीब एक घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने अंबिकापुर शहर की जल निकासी व्यवस्था की कमजोरियां उजागर कर दीं। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पहली ही तेज बारिश में कई स्थानों पर जलभराव होने से मानसून पूर्व तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। जलभराव को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष का आरोप है कि बारिश से पहले नालियों की समुचित सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसका परिणाम पहली ही बारिश में सामने आ गया। पार्षद शुभम जायसवाल ने कहा कि नगर निगम को मानसून से पहले जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यक सुधार कार्य करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के कई व्यापारियों ने दुकानों के सामने पेवर ब्लॉक बिछाकर नालियों को ढंक दिया है, जिससे वर्षा जल की निकासी बाधित हो रही है। यदि ऐसे अतिक्रमण और अवरोध समय रहते नहीं हटाए गए तो आगामी दिनों में भारी बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि संगम चौक और महामाया चौक जैसे प्रमुख क्षेत्रों की नालियों की पिछले डेढ़ से दो वर्षों से समुचित सफाई नहीं हुई है। वहीं एमजी रोड स्थित वूमेन्स हॉस्टल और पीजी कॉलेज के आसपास लगातार जलभराव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अब तक कोई प्रभावी पहल नहीं हुई है।

जलजली में पार्किंग शुल्क पर सोशल मीडिया में बवाल

50 वाहन पार्किंग,10 प्रवेश शुल्क पर उठा सवाल...
रसीद,जवाबदेही और राशि के उपयोग पर पारदर्शिता की मांग...

-संवाददाता-
मैनपाट,02 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जलजली (मैनपाट) में पर्यटकों से लिए जा रहे पार्किंग एवं प्रवेश शुल्क को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोगों ने पार्किंग व्यवस्था,शुल्क वसूली और रसीद की वैधता पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच कराने तथा वसूली में पारदर्शिता लाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पार्किंग पर्ची के अनुसार चार पहिया वाहन के लिए 50 पार्किंग शुल्क तथा प्रति व्यक्ति 10 प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। आपत्ति इस बात पर भी जताई जा रही है कि पार्किंग शुल्क लेने के बावजूद पर्ची में वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्किंग संचालक द्वारा नहीं लेने का उल्लेख है। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि रसीद में वाहन का नंबर तक दर्ज नहीं किया जा रहा, जिससे इसकी विश्वसनीयता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने पूछा है कि यदि वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्किंग संचालक की नहीं है, तो फिर पार्किंग शुल्क किस आधार पर लिया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी मांग की कि पार्किंग और प्रवेश शुल्क से प्राप्त राशि का हिसाब सार्वजनिक किया जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि यह राशि किस विभाग या संस्था के खाते में जमा हो रही है और उसका उपयोग किस कार्य में किया जा रहा है। कुछ टिप्पणियों में यह भी आरोप लगाया गया कि सड़क की स्थिति खराब होने के बावजूद पर्यटकों से शुल्क वसूला जा रहा है। कई लोगों ने पार्किंग व्यवस्था को 'मनमानी' बताते हुए इसकी जांच कराने और नियमों के अनुरूप व्यवस्था संचालित करने की मांग की है। कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में वन विभाग पर भी आरोप लगाए गए हैं, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

प्रशासन से स्पष्ट जवाब की अपेक्षा

सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद के बीच अब लोगों की नजर संबंधित वन विभाग और जिला प्रशासन पर है। नागरिकों का कहना है कि यदि शुल्क अधिकृत है तो उसके संबंध में स्पष्ट आदेश, निर्धारित दरें, वसूली का अधिकार, राशि का उपयोग तथा पार्किंग व्यवस्था की जवाबदेही सार्वजनिक की जानी चाहिए। वहीं यदि किसी स्तर पर अनियमितता है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

गैंता से दोस्त पर जानलेवा हमला, अस्पताल पहुंचते ही हो गई मौत

लुंड्रा के बरगीडीह गांव की घटना,खेत से लौटे परिजन घायल को मेडिकल कॉलेज लाए, डॉक्टर ने मृत घोषित किया

-संवाददाता-
लुण्ड्रा,02 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगीडीह में गुरुवार को एक ग्रामीण ने अपने ही साथी की गैंता से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने ग्रामीणों से कहा कि उसने जीतू को मार दिया है और अब जेल जाएगा। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम बरगीडीह निवासी जीतू नागेश (45), पिता सोमारू नागेश, गुरुवार को घर पर था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य धान की रोपाई के लिए खेत गए हुए थे। इसी दौरान वह पड़ोस में रहने वाले अपने साथी बुधराम के घर के पास पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर बुधराम ने गैंता से जीतू पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद आरोपी ने आसपास के लोगों को बताया कि उसने जीतू की हत्या कर दी है और अब जेल जाएगा। इसके बाद वह अपने घर जाकर सो गया। इधर,घटना की सूचना मिलने पर खेत में काम कर रहे परिजन मौके पर पहुंचे। घायल जीतू को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल को अस्पताल पहुंचाने में आरोपी के बेटे ने भी सहयोग किया। घटना की सूचना मिलते ही लुंड्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

खाना बनाते समय आग से झुलसी रीडर की पत्नी की मौत

प्रतापपुर में किराए के मकान में हुआ हादसा,मिशन अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ा दम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

प्रतापपुर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में पदस्थ रीडर की पत्नी की खाना बनाते समय आग से झुलसने से मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला का अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, प्रतापपुर एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर सीताराम ने पुलिस को बताया कि 1 जुलाई की रात करीब 8 बजे वह ड्यूटी से लौटकर किराए के मकान में आया था और कमरे में आराम कर रहा था। इसी दौरान उसकी 45 वर्षीय पत्नी श्यामपति रसोई में खाना बना रही थी। कुछ देर बाद रसोई से चीखने की आवाज सुनकर वह वहां पहुंचा तो देखा कि पत्नी की नाइटी में आग लग गई थी और वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। सीताराम ने शोर मचाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया। आवाज सुनकर मकान मालिक भी मौके पर पहुंच गए। सभी ने मिलकर आग बुझाई और महिला को तत्काल प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अंबिकापुर रेफर कर दिया।

27 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मिला पीपीओ

जिला शिक्षा अधिकारी ने पेंशन भुगतान आदेश सौंपकर दी स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की शुभकामनाएं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शिक्षा विभाग में लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए 27 प्राचार्यों, प्रधानपाठकों एवं कर्मचारियों को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्रदान किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश झा ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पीपीओ सौंपते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण जीवन की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में एक जुलाई को सेवानिवृत्त हुए नौ प्राचार्यों, सत्रह प्रधानपाठकों तथा एक भृत्य को पीपीओ वितरित किया गया।

पीपीओ जारी होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन संबंधी औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें समय पर पेंशन सहित अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। पीपीओ प्राप्त करने वालों में प्राचार्य मो. साहिद अंसारी, अशोक कुमार वर्मा, संतोष कुमार श्रीवास्तव, छोटू एक्का, श्याम प्यारी बुनकर, प्रताप नाराय, नरेन्द्र अम्बष्ट, अरुण राय एवं ललन कुशवाहा शामिल रहे। वहीं प्रधानपाठकों में ममता गुप्ता, शुभाशीष मुखर्जी, अलका अग्रवाल, अंबिका प्रसाद सोनी, कृष्ण कुमार अचगले, देवलाल राम यादव, हबीबुर्र रहमान, कुलन राम पैकरा, लक्षन राम सिंह, लाल मोहर सिंह, मगदली तिग्गा, रामलाल प्रसाद, जगदीश सिंह, अनिल राम प्रजापति, तेजबहादुर सिंह, माया सिन्हा एवं देवनाथ रात को पीपीओ प्रदान किया गया। इसके अलावा भृत्य तसउवर हुसैन को भी पेंशन भुगतान आदेश सौंपा गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश झा ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवानिवृत्ति सेवा का अंत नहीं बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने सभी के उत्तम स्वास्थ्य,दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि विभाग उनके योगदान को सदैव स्मरण रखेगा।

600 बच्चों का कुपोषण दूर करने का दावा,अदाणी विद्या मंदिर के मॉडल पर उठेंगे कई सवाल भी...

एक साल के 'हेल्थ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट' के सफल होने का दावा लेकिन मेडिकल डेटा,स्वतंत्र मूल्यांकन और सरकारी पुष्टि सामने नहीं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा के साल्ही स्थित अदाणी फाउंडेशन द्वारा संचालित अदाणी विद्या मंदिर ने दावा किया है कि उसके एक वर्ष तक चले 'हेल्थ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट' से 14 गांवों के 600 विद्यार्थियों में कुपोषण और शारीरिक कमजोरी की समस्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विद्यालय का कहना है कि अब प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को चक्कर आने की शिकायत पूरी तरह समाप्त हो गई है। हालांकि इस दावे के साथ कई ऐसे प्रश्न भी जुड़े हैं,जिनका जवाब सार्वजनिक होना बाकी है। विद्यालय के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रतिदिन 15 से 20 बच्चों को प्रार्थना सभा के दौरान कमजोरी और चक्कर आने की शिकायत होती थी। जांच में अधिकांश बच्चों का वजन सामान्य से कम पाया गया। इसके बाद डायटीशियन की सलाह पर विशेष पोषण योजना और नियमित व्यायाम कार्यक्रम शुरू किया गया। योजना के तहत बच्चों को प्रतिदिन दूध के साथ माल्ट आधारित पेय, सोयाबीन, मूंग, चना, मौसमी फल और संतुलित भोजन दिया गया। साथ ही नियमित व्यायाम कराया गया। विद्यालय का दावा है कि 12 महीने बाद बच्चों का वजन बढ़ा, सहनशक्ति बेहतर हुई और चक्कर आने की समस्या समाप्त हो गई।

दावे के साथ कई सवाल भी : विद्यालय ने इसे 'एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट' बताया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अध्ययन किस वैज्ञानिक पद्धति से किया गया, कितने बच्चों की चिकित्सकीय जांच पहले और बाद में हुई, किस संस्था या विशेषज्ञ ने परिणामों का स्वतंत्र सत्यापन किया तथा क्या यह अध्ययन किसी मेडिकल या सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा प्रमाणित है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिन बच्चों को पहले कुपोषित बताया गया था, उनका पोषण स्तर किस सरकारी या चिकित्सकीय मानक (जैसे डब्ल्यूएचओ या आईसीएमआर) के आधार पर निर्धारित किया गया और परियोजना पूरी होने के बाद उनमें कितना मात्रात्मक सुधार दर्ज किया गया।

सरकारी आंकड़ों से तुलना जरूरी

सरगुजा सहित प्रदेश के कई आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। ऐसे में यदि किसी विद्यालय ने वास्तव में एक वर्ष में 600 बच्चों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है, तो इस मॉडल का स्वतंत्र मूल्यांकन कर इसे सरकारी स्तर पर भी अपनाने की संभावना तलाशनी चाहिए। वहीं यदि यह केवल संस्थागत दावा है, तो उसके समर्थन में विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट और शोध निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने चाहिए। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह मॉडल ग्रामीण बच्चों के स्वास्थ्य सुधार का प्रभावी उदाहरण है। हालांकि सार्वजनिक हित में इस तरह के दावों की पारदर्शी जांच और स्वतंत्र पुष्टि भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह पहल वास्तव में एक सफल स्वास्थ्य मॉडल है या केवल संस्थागत उपलब्धि का दावा।

वीबी-जी राम जी योजना का शुभारंभ,अब 125 दिन रोजगार और 300 रुपये दैनिक मजदूरी

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल बोले...सशक्त गांव से ही विकसित भारत का सपना होगा साकार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिला पंचायत सभाकक्ष में गुरुवार को विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर योजना का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि योजना का उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीणों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि अब ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा तथा मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है।

फायर सेफ्टी पर प्रशासन सख्त...होटल,मॉल, कोचिंग सेंटर और बहुमंजिला भवनों की होगी जांच

कलेक्टर ने गठित किया संयुक्त दल,प्रवेश-निकास व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा मानकों की होगी पड़ताल

हाल के अग्निकांडों के बाद प्रशासन की बड़ी पहल,नियमों की अनदेखी करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिले में सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले के सभी बहुमंजिला आवासीय भवनों, कोचिंग सेंटरों, ट्यूशन कक्षाओं, होटल, लॉज, मॉल, व्यावसायिक परिसरों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों की फायर सेफ्टी एवं सुरक्षा मानकों की जांच के लिए संयुक्त जांच दल का गठन किया है। जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों का सुरक्षित निकास संभव हो तथा भवनों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हों। जारी आदेश के अनुसार गठित दल का नेतृत्व अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) अम्बिकापुर करेंगे। दल में नगर पुलिस अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी) के कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम के कार्यपालन अभियंता तथा एसडीआरएफ के अग्निशमन अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह दल विभिन्न भवनों का स्थल निरीक्षण कर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का परीक्षण करेगा।

इन बिंदुओं पर होगी विशेष जांच : जांच के दौरान भवनों में आपातकालीन प्रवेश एवं निकास मार्ग, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं उनकी कार्यशील स्थिति,फायर अलार्म सिस्टम,विद्युत सुरक्षा,आपदा की स्थिति में निकासी की व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी भवन में निर्धारित मानकों का पालन नहीं पाया जाता है तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

हालिया घटनाओं के बाद बढ़ी सतर्कता : देश के विभिन्न राज्यों में हाल के वर्षों में कोचिंग सेंटरों, अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक भवनों में हुई आगजनी की घटनाओं में बड़ी जनहानि हुई है। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा मानकों की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में सरगुजा जिला प्रशासन ने भी व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।

भवन संचालकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी : प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि केवल अग्निशमन यंत्र लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका नियमित रखरखाव, कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण तथा भवनों में सुरक्षित निकास व्यवस्था सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। जांच अभियान के बाद कई संस्थानों को सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

छात्र संसद ने ली शपथ,जिम्मेदारी निभाने और नेतृत्व का दिया गया संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चयनित छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने छात्र प्रतिनिधियों को नेतृत्व,अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की सीख दी। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना नृत्य और दीप प्रज्ज्वलन से हुई। विद्यालय के बैगपाइपर बैंड ने मुख्य अतिथि की अगवानी की। प्राचार्य डॉ. सि. जेस्सी थेक्कन ने छात्र संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई तथा बैज और सैश पहनाकर सम्मानित किया। छात्र संसद में अमोघवर्ष पाण्डेय एवं अम्बिका सिंह को अध्यक्ष,आकर्ष सिंघल एवं शाम्भवी सिंह को उपाध्यक्ष, सिद्धि सिद्ध विद्या को सचिव तथा आलिन्द अग्रवाल को सहसचिव का दायित्व सौंपा गया। मुख्य अतिथि विनय कुमार अग्रवाल ने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि नेतृत्व से पीछे हटने के बजाय उसे अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से असफलताओं से सीख लेकर निरंतर प्रयास करते रहने का आह्वान किया। रोहिणी उपग्रह मिशन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआती असफलताओं के बाद भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और अंततः सफलता हासिल की। उन्होंने सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करने और आत्ममूल्यांकन की आदत विकसित करने की सलाह भी दी। प्राचार्य डॉ. सि. जेस्सी थेक्कन ने कहा कि छात्र संसद का बैज केवल सम्मान नहीं, बल्कि सेवा,अनुशासन,ईमानदारी और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। उन्होंने छात्र प्रतिनिधियों से विद्यालय और समाज के लिए आदर्श नेतृत्व प्रस्तुत करने का आह्वान किया। समारोह के अंत में मुख्य अतिथि का शॉल एवं स्मृति-चिह्न देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका अनुराधा अग्रवाल ने किया, जबकि अनुपम दुबे ने आभार प्रदर्शन किया। राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं विजय पैकरा आ श्री दिल भरन राम आयु 48 वर्ष, जाति कवर,निवास का पता- ग्राम बकना खुर्द खालधारा, थाना एवं तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. पिन 497001 का निवासी हूँ । मेरी पुत्री का वास्तविक नाम चंचल पैकरा/ Chanchal Paikra है तथा वह इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाती है। मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेज में भी उसका सही नाम अंकित है। मेरे पुत्री का आधार कार्ड बना है, जिसका नं0 9861 86742060 है, जिसमें उसका घरेलू नाम मीतल पैकरा / Mital Paikra अंकित हो गया जो गलत है। मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या 9861 6674 2060 में अंकित उसका नाम मीतल पैकरा / Mital Paikra के स्थान पर उसका सही नाम चंचल पैकरा / Chanchal Paikra अंकित किये जाने एवं शासकीय गजट व राजपत्र प्रकाशन हेतु स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता
विजय पैकरा

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राजी बाई पति खसरू उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम बकनाकला तह0 लुण्ड्रा जिला सरगुजा छ0ग0 का उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।

यह कि मेरे पुत्र अंजीत कुमार (ANJIT KUMAR) के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अजीत कुमार (AJIT KUMAR) दर्ज हो गया है, जो गलत है, जिसका आधार नम्बर 726052568836 है।

कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा दसवीं के अंकसूची में उसका नाम अंजीत कुमार (ANJIT KUMAR) दर्ज है जो सत्य एवं सही है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका सही नाम अंजीत कुमार (ANJIT KUMAR) दर्ज कराने हेतु स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता
राजी बाई

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका पंकज आ0/पति राधेगोविन्द ठाकुर जाति नाई, निवासी दर्रीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-दर्रीपारा, शीट नम्बर -10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3921/2 रकबा 0.47 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-13.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है । नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 24.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रीमती मधुरानी अग्रवाल आ0/ पति दिनेश अग्रवाल जाति, निवासी बाबूपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - बाबूपारा, शीट नम्बर-9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट 3467/4866/115 रकबा 7500 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-15.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 30.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका विष्णु प्रसाद सांडिल्य आ0 / पति स्व0 रामप्रसाद सांडिल्य जाति, निवासी शीतला वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-शीतला वार्ड, शीट नम्बर-9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3283, 3284/1, 3293 रकबा 0.35, 0.04, 0.11 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3. 2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-15.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 30.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

रामगढ़ महोत्सव में रामभक्ति प्रकृति और लोकसंस्कृति से सराबोर रहा सरस कवि-सम्मेलन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
रामगढ़ महोत्सव के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सरस कवि-सम्मेलन में रामभक्ति,प्रकृति संरक्षण, लोकसंस्कृति और मानवीय मूल्यों पर आधारित काव्य प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ गीतकार रंजीत सारथी की सरगुजिहा श्रीराम वंदना से हुआ। मंच संचालन संतोष दास 'सरल' ने किया। विभिन्न कवियों ने भगवान राम के आदर्शों,निष्काम कर्म,नारी सम्मान,रामराज्य और भारतीय संस्कृति पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत कीं। वरिष्ठ गीतकार संतोष दास 'सरल' ने अपने सरगुजिहा गीत 'चल न संगी रामगढ़ देखे-बुले जाबो...' के माध्यम से रामगढ़ और सरगुजा की सांस्कृतिक विरासत का सुंदर चित्रण किया। वहीं आशुकवि विनोद हर्ष ने 'सतपुड़ा-सी वादियां, छोटे-मोटे अबूझमाड़ रहने दो, बदौलत इन्हीं के है जलचक्र, धरा पर आषाढ़ रहने दो' कविता के माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के अनेक वरिष्ठ कवियों और कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं से समां बांधा।

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)

// सार्वजनिक उद्घोषणा/ईश्तहार //

क्रमांक/2273/वाचक-2/2026
सूरजपुर दिनांक 03/07/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी /नगरवासी ग्राम/नगर ग्रा0पं0 डेडरी प0ह0नं0...तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुध राम पिता दलीप सिंह जाति गोंड़ निवासी ग्राम डेडरी पोस्ट डेडरी थाना सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0) नें अपनें दादी फुलकुवंर पिता/पति रामनारायण जन्म/मृत्यु तिथि 05/10/2009 मृत्यु स्थान डेडरी के मृत्यु पत्र हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है,जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति/आक्षेप हो तो वे स्वंय अथवा अपनें अभिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 16/07/2026 दिन शुक्रवार को उपस्थित होकर दावा / आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा/आपत्ति/आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील — नायब तहसीलदार, उप तहसील मानी, तहसील-सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका चिराग चोपड़ा आश्र / पति मनोरथ चोपड़ा जाति, निवासी चोपड़ापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-चोपड़ापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 9/119 रकबा $0.01^{3/4}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-03.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 18.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी बरियों जिला-बलरामपुर-रा0गं0,छ0ग0

रा0मा0क्र0- /-121/2025-26
ग्राम- अमडीपारा पह0नं0
उप तह0 - बरियों

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम अमडीपारा पह0नं0 उप तहसील बरियों जिला बलरामपुर रा0गंज को सूचित किया जाता है कि आवेदक मानसाय राम आ0/पति.. स्व बंधन राम जाति कोरवा निवासी ग्राम अमडीपारा तहसील- राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा स्वयं के पिता बंधन राम आ0 घासी राम का मृत्यु दिनांक है। किन्तु जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वश कार्य व्यस्तता के कारण 08.06.2009 को ग्राम अमडीपारा घर में हुई पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र पेश ।

उपरोक्त जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र में उज्जर आपत्ति या दावा हो या हितबद्ध पक्षकार हो तो वह स्वंय, अथवा वैध अभिकर्ता अथवा अभिभाषक के दिनांक-26/07/2026 को न्यायालयीन समय में दावा या आपत्ति हो तो पेश कर सकता है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

अतः आज दिनांक- 12/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुहर से जारी किया गया।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी, बरियों, जिला बलरामपुर-रा0गंज

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)

// सार्वजनिक उद्घोषणा/ईश्तहार //

क्रमांक/2265/वाचक-2/2026
सूरजपुर दिनांक 01/07/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी /नगरवासी ग्राम /नगर ग्रा0पं0 पोड़ी प0ह0नं016 तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक देव सिंह पिता जगदीश जाति गोंड़ निवासी ग्राम पोड़ी पोस्ट केतका थाना सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0) नें अपनें पुत्र/पुत्री माता गौटिन पति जगदीश मृत्यु तिथि 05/03/2018 स्थाना पोड़ी के मृत्यु पत्र हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति/आक्षेप हो तो वे स्वंय अथवा अपनें अभिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 15/07/2026 दिन गुरूवार को उपस्थित होकर दावा / आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा/आपत्ति/आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील — तहसीलदार, सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)

// सार्वजनिक उद्घोषणा/ईश्तहार //

क्रमांक/2257 /वाचक-2/2026
सूरजपुर दिनांक 24/06/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी /नगरवासी ग्राम /नगर ग्रा0पं0 नयनपुर प0ह0नं0...तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक बुधू सिंह पिता विदूर सिंह जाति गोंड़ निवासी ग्राम नयनपुर पोस्ट.....थाना सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0) नें अपनें पुत्र/पुत्री कन्दरईहा पिता मांझी जन्म/मृत्यु तिथि 01/02/2002 मृत्यु स्थान नयनपुर के मृत्यु पत्र हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति/आक्षेप हो तो वे स्वंय अथवा अपनें अभिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 20/07/2026 दिन सोमवार को उपस्थित होकर दावा / आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा/आपत्ति/आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील — नायब तहसीलदार, उप तहसील मानी, तहसील-सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)

// सार्वजनिक उद्घोषणा/ईश्तहार //

क्रमांक/2256 /वाचक-2/2026
सूरजपुर दिनांक 24/06/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी /नगरवासी ग्राम/नगर ग्रा0पं0 नयनपुर प0ह0नं0...तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक बुधू सिंह पिता विदूर सिंह जाति गोंड़ निवासी ग्राम नयनपुर पोस्ट.....थाना सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0) नें अपनें पुत्र/पुत्री दिलबसिया पिता/पति कन्दरईहा जन्म/मृत्यु तिथि 02/03/2005 मृत्यु स्थान नयनपुर के मृत्यु पत्र हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है,जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति/आक्षेप हो तो वे स्वंय अथवा अपनें अभिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 20/07/2026 दिन सोमवार को उपस्थित होकर दावा / आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा/आपत्ति/आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील — नायब तहसीलदार, उप तहसील मानी, तहसील-सूरजपुर

रपटा में 15 लाख खर्च...फिर भी पुल तक पहुंचना दूभर,एप्रोच रोड बनी सबसे बड़ी बाधा

रपटा बन गया,सड़क नहीं...बरसात में फिर ठप्प हुआ आवागमन...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर 02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। गोबरी नदी पर लगभग 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित स्थायी रपटा पुल को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच अब एक नया विवाद सामने आ गया है, लगातार समाचार प्रकाशित होने, जिला कलेक्टर द्वारा मामले का संज्ञान लेने और स्थल निरीक्षण के बाद विभाग ने जैसे-तैसे रपटा का निर्माण तो पूरा कर दिया, लेकिन आज भी यह आम लोगों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं हो पाया है, कारण है–रपटा के दोनों ओर करीब 300-300 मीटर तक एप्रोच मार्ग का अधूरा निर्माण। बरसात शुरू होते ही दोनों ओर डाली गई मिट्टी दलदल में बदलने लगी है, परिणामस्वरूप रपटा तक पहुंचना ही लोगों के लिए चुनौती बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत ऐसी है कि वाहन चलाना मानो कीचड़ में तैरने जैसा हो गया है। ऐसे में लाखों रुपये खर्च कर बनाया गया रपटा केवल दिखावे का निर्माण बनकर रह गया है।

'घटती-घटना' की मुहिम के बाद हरकत में आया प्रशासन

दैनिक 'घटती-घटना' ने पिछले कई महीनों से इस मामले को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया, समाचारों में यह सवाल उठाया गया था कि गोबरी नदी पर रपटा निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन एप्रोच रोड के बिना इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा,लगातार प्रकाशित खबरों के बाद जिला कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को स्थल निरीक्षण के निर्देश दिए, निरीक्षण के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई और रपटा तैयार कर दिया गया,लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य–दोनों ओर मजबूत एप्रोच मार्ग का निर्माण–आज भी अधूरा है।

15 लाख का खर्च,लेकिन तकनीकी मानकों का पालन हुआ?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस निर्माण कार्य पर लगभग 15 लाख रुपये खर्च दर्शाया गया है, उसमें एप्रोच मार्ग को भी मजबूत बनाया जाना चाहिए था,तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी रपटा या पुल की उपयोगिता तभी होती है जब उससे जुड़ी संपर्क सड़क मजबूत और सभी मौसम में उपयोग योग्य हो,इसके लिए जीएसबी,डब्ल्यूएमएम,स्टोन डस्ट जैसी परतें बिछाई जाती हैं, ग्रामीणों का सवाल है कि यदि यह कार्य नहीं किया गया तो क्या निर्माण तकनीकी मानकों के अनुरूप पूरा माना जा सकता है?

जनप्रतिनिधि ने भी उठाई आवाज

मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद पंचायत भैयाथान के सदस्य एवं सहकारिता एवं उद्योग विकास समिति के सभापति राजकुमार गुप्ता ने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में कहा गया है कि रपटा बनने के बावजूद दोनों ओर एप्रोच मार्ग नहीं होने से किसान, छात्र,महिलाएं और आम नागरिक प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं, उन्होंने बरसात से पहले दोनों ओर संपर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग की है।

रपटा तैयार, लेकिन सड़क ऐसी कि पहुंचना मुश्किल-

स्थानीय लोगों के अनुसार रपटा तक पहुंचने वाली सड़क के दोनों ओर केवल मिट्टी डालकर छोड़ दी गई है, लगभग 300-300 मीटर तक सड़क पर न तो जीएसबी डाली गई और न ही डब्ल्यूएमएम या स्टोन डस्ट का उपयोग किया गया,बरसात की पहली बारिश में ही पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई। दोपहिया वाहन फिसल रहे हैं, चार पहिया वाहन धंस रहे हैं और पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है,ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुल तक पहुंचना ही संभव नहीं होगा तो पुल बनने का उद्देश्य क्या रह जाएगा?

बारिश में फिर कट सकता है संपर्क...

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि शीघ्र एप्रोच रोड को मजबूत नहीं किया गया तो लगातार बारिश में मिट्टी बह सकती है और रपटा तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह बाधित हो सकता है, ऐसी स्थिति में जिन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी, उन्हें फिर पुराने वैकल्पिक और जोखिम भरे रास्तों का सहारा लेना पड़ेगा।

क्या केवल बिल पास कराने के लिए हुआ निर्माण?

ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि यदि निर्माण कार्य तकनीकी रूप से पूरा नहीं था तो उसे पूर्ण कैसे मान लिया गया? लोगों का आरोप है कि पुल का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन सबसे जरूरी एप्रोच रोड अधूरी छोड़ दी गई, लोगों का कहना है कि इससे यह सवाल खड़ा होता है कि कहीं निर्माण कार्य केवल बिल भुगतान और औपचारिकता पूरी करने तक सीमित तो नहीं रहा?

'घटती-घटना' के बड़े सवाल

- जब एप्रोच रोड तैयार नहीं थी तो निर्माण कार्य पूर्ण कैसे माना गया?
- क्या बिना जीएसबी, डब्ल्यूएमएम या स्टोन डस्ट के सड़क उपयोग योग्य मानी जा सकती है?
- क्या निर्माण कार्य का तकनीकी निरीक्षण हुआ था?
- क्या विभाग ने गुणवत्ता परीक्षण कराया?
- यदि पहली ही बारिश में सड़क कीचड़ में बदल गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
- क्या भुगतान से पहले कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया?
- क्या अब भी एप्रोच रोड निर्माण के लिए अलग से राशि स्वीकृत होगी?

कलेक्टर के संज्ञान के बाद बना रपटा,लेकिन एप्रोच रोड ने खोल दी निर्माण की पोल

रपटा तैयार,लेकिन अधूरे एप्रोच ने करोड़ों की व्यवस्था पर खड़े किए सवाल

रपटा तो बना,लेकिन जनता के लिए नहीं! दोनों ओर 300-300 मीटर कीचड़ में फंसा आवागमन

बरसात में बेकार साबित हुआ 15 लाख का रपटा, एप्रोच रोड के बिना अधूरी रही परियोजना

क्या सिर्फ बिल पास कराने के लिए बना रपटा? एप्रोच रोड के बिना लाखों की परियोजना सवालों में

'घटती-घटना' की लगातार खबरों,कलेक्टर के संज्ञान और निरीक्षण के बाद बना रपटा

जनता पूछ रही है–पुल बन गया,लेकिन यदि उस तक पहुंचने का रास्ता ही दलदल में है तो 15 लाख रुपये की इस परियोजना का वास्तविक लाभ आखिर किसे मिला?

अब क्या चाहते हैं ग्रामीण?-

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि रपटा के दोनों ओर तत्काल जीएसबी, डब्ल्यूएमएम अथवा स्टोन डस्ट डालकर सड़क को मजबूत बनाया जाए, तकनीकी टीम से निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराई जाए, यदि निर्माण में लापरवाही मिली हो तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की जवाबदेही तय की जाए, बरसात के दौरान सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान किया जाए।

अब प्रशासन की परीक्षा...

गोबरी नदी पर बने रपटा पुल का निर्माण निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों के लिए राहत का माध्यम बन सकता है,लेकिन तभी जब उससे जुड़ी संपर्क सड़क भी उपयोगी हो, वर्तमान स्थिति में पुल तैयार है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता ही दलदल में बदल चुका है,ऐसे में लोगों का कहना है कि 'रपटा तो बन गया,लेकिन सड़क नहीं बनी, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस अधूरे निर्माण को कब तक पूर्ण कराते हैं, ताकि लाखों रुपये की लागत से बना यह रपटा वास्तव में जनता के काम आ सके,न कि केवल सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण परियोजना बनकर रह जाए।

अभाविप चिरमिरी एवं मनेंद्रगढ़ में नई ऊर्जा का संचार सत्र 2026-27 की नवीन नगर कार्यकारिणी घोषित

युवा नेतृत्व को मिली जिम्मेदारी,छात्र हित,संगठन विस्तार और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मिलेगी नई दिशा

-संवाददाता-

एमसीबी,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा सत्र 2026-27 के लिए चिरमिरी एवं मनेंद्रगढ़ नगर इकाइयों की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई,संगठन ने युवा कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपते हुए छात्र हितों की रक्षा,संगठन विस्तार, सामाजिक नेतृत्व एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाने का संदेश दिया, नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ दोनों नगरों में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का वातावरण देखने को मिला।

चिरमिरी नगर इकाई को मिला नया नेतृत्व- चिरमिरी नगर की घोषित कार्यकारिणी में अनुपम पांडे को नगर अध्यक्ष तथा सुमित केशरवानी को नगर मंत्री का दायित्व सौंपा गया,वहीं कुलदीप पांडेय,कोमल सिंह एवं प्रतिभा गुप्ता को सह नगर मंत्री बनाया गया, इसके अलावा नैतिक कुमार को कार्यालय मंत्री,अभिषेक कुमार को महाविद्यालय प्रमुख, प्रफुल्ल केशरवानी को विद्यालय प्रमुख,ओम कुमार को एसएफएस प्रमुख,मनीषी अग्रहरि को एसएफडी प्रमुख,आशु कुमार को एनसीसी प्रमुख,तनय कुमार को एनएसएस प्रमुख, साक्षी कुमारी को आरकेएम प्रमुख तथा निखिल जायसवाल को सोशल मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई,नगर कार्यकारिणी में सोहेल,खुशबू सिंह, दीक्षा यादव,शान्या, सत्या,अंशु,प्रियांशु विश्वकर्मा एवं राजू को भी शामिल किया गया,इस अवसर पर नवनियुक्त नगर अध्यक्ष अनुपम पांडे ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता छात्र-छात्राओं के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन तथा राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित भाव से कार्य करता है,उन्होंने कहा कि संगठन की विचारधारा एवं सेवा कार्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सभी कार्यकर्ताओं की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मनेंद्रगढ़ नगर इकाई ने भी संभाली नई जिम्मेदारियां–मनेंद्रगढ़ नगर कार्यकारिणी में राज नामदेव को नगर मंत्री तथा महेश कौशिक एवं सोनाल कुमार को सह नगर मंत्री का दायित्व सौंपा गया,इसके साथ ही रागिनी देवांगन,साक्षी देवांगन,मोनित लालपुरे (एसएफडी प्रमुख),अभिषेक कुमार सिंह (एसएफएस प्रमुख),आदित्य शर्मा (आरकेएम प्रमुख),राहुल प्रजापति (विद्यालय प्रमुख),कृष्ण पनिका (एनएसएस प्रमुख),मनोज तिवारी (कार्यालय मंत्री),शुभम सिंह (सोशल मीडिया प्रमुख) तथा मानसी अग्रवाल को नगर कार्यकारिणी में विभिन्न जिम्मेदारियां प्रदान की गई,महाविद्यालय प्रमुख के पद की घोषणा आगामी समय में किए जाने की जानकारी दी गई।

संगठन विस्तार और छात्र हितों पर रहेगा विशेष फोकस– कार्यक्रम के दौरान दोनों नगरों के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए संगठन को और अधिक सक्रिय,प्रभावी एवं छात्र-केंद्रित बनाने का संकल्प लिया,वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थी परिषद केवल छात्र संगठन नहीं,बल्कि राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जागरूकता का सशक्त माध्यम है,आगामी सत्र में विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान, शैक्षणिक गतिविधियों,व्यक्तित्व विकास,सामाजिक सेवा एवं संगठन विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी, चिरमिरी में आयोजित कार्यक्रम में जिला संयोजक बलबीर पुशाम एवं जिला संगठन मंत्री अशोक यादव सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम् एवं भारत माता के जयघोष के साथ हुआ,वहीं मनेंद्रगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सुनीता,राजबली, देव कुमार,अमन, सुजल, विकास, मोनू सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।

अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर जिला शिक्षा अधिकारी विनोद राय को भावभीनी विदाई,शिक्षा जगत ने दी सम्मानपूर्ण विदाई...

-संवाददाता-

कोरिया,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। जिला शिक्षा अधिकारी श्री विनोद राय के अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के अवसर पर जिला शिक्षा कार्यालय में भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का आयोजन जीतेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुआ,जिसमें जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अनेक अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे, पूरे कार्यक्रम का वातावरण सम्मान, आत्मीयता एवं भावनात्मक स्मृतियों से ओतप्रोत रहा। समारोह में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विनोद राय के लंबे प्रशासनिक अनुभव, सरल व्यक्तित्व,अनुशासित कार्यशैली तथा शिक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में विभाग ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, वक्ताओं ने कहा कि श्री राय ने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए, उनके कुशल प्रशासन और सकारात्मक कार्यशैली से विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निरंतर प्रेरणा मिलती रही,अपने विदाई उद्बोधन में श्री विनोद राय ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्नेह, सहयोग एवं सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया, उन्होंने विशेष रूप से जीतेन्द्र गुप्ता के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके निरंतर मार्गदर्शन,सक्रिय सहभागिता और समर्पित कार्यशैली के कारण ही विभाग द्वारा संचालित 'मिशन 100' अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सका। उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति केवल एक व्यक्ति के प्रयासों से संभव नहीं होती,बल्कि पूरी टीम की एकजुटता, समन्वय और सकारात्मक सोच ही सफलता का आधार बनती है, श्री राय ने कहा कि जीतेन्द्र गुप्ता ने पूरे अभियान के दौरान न केवल प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया, बल्कि अपनी दूरदर्शिता, कार्यनिष्ठा एवं टीम भावना से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाया, उनके नेतृत्व और सहयोग ने मिशन 100 को नई दिशा एवं गति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सका,उन्होंने विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से उनका कार्यकाल सदैव यादगार बना रहेगा,कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कर्मचारियों ने श्री विनोद राय का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति-चिह्न भेंटकर सम्मान किया तथा उनके साथ बिताए गए कार्यकाल की अनेक यादों को साझा किया, कई कर्मचारियों ने उनके सरल व्यवहार, सहज उपलब्धता और कार्य के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण को विभाग की बड़ी पूंजी बताया, समारोह के अंत में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विनोद राय के स्वस्थ, सुखमय एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी,उपस्थित सभी लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका अनुभव और मार्गदर्शन भविष्य में भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

चापा-खुरा टीकाकरण अभियान में करोड़ों का खेल?

खड़गवां से उठे सवाल पूरे एमसीबी जिले तक पहुंचे, किसानों का दावा- 'न टीम आई, न टीका लगा', फिर भी पोर्टल पर दर्ज हो गई शत-प्रतिशत उपलब्धि

ग्रामवार भौतिक सत्यापन हो तो खुल सकती है फर्जी रिपोर्टिंग की बड़ी पोल, स्वतंत्र जांच की उठी मांग

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां/एमसीबी 02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। पशुधन को संक्रामक एवं जानलेवा चापा-खुरा (फुट एंड माउथ डिजीज-एफएमडी) रोग से बचाने के लिए केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाता है,इस अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र पशु तक टीका पहुंचाकर बीमार की रोकथाम करना होता है,लेकिन मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले, विशेषकर खड़गवां विकासखंड में इस अभियान की सफलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्षेत्र के अनेक पशुपालकों का आरोप है कि विभाग ने सरकारी रिकॉर्ड और ऑनलाइन पोर्टल पर लगभग 100 प्रतिशत टीकाकरण का दावा कर दिया, जबकि वास्तविकता में बड़ी संख्या में पशुओं को टीका लगाया ही नहीं गया, किसानों का कहना है कि न तो टीकाकरण दल उनके गांव पहुंचा और न ही उनके पशुओं का टीकाकरण हुआ, फिर भी रिकॉर्ड में उनके पशुओं को टीका लगा हुआ दर्शा दिया गया, यदि इन आरोपों में सच्चाई है,तो यह मामला केवल विभागीय लापरवाही तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि सरकारी धन के उपयोग, रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और पशुधन सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है।

रिकॉर्ड में सफलता,जमीन पर अधूरा अभियान?-कई गांवों के पशुपालकों का दावा है कि उन्होंने अपने पशुओं को कोई टीका लगते नहीं देखा, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उनके यहां टीकाकरण टीम कभी पहुंची ही नहीं,जबकि विभागीय रिकॉर्ड में उनके गांव का कार्य पूर्ण दिखाया गया है,यदि यह स्थिति सही है, तो सवाल उठता है कि क्या शासन को वास्तविक प्रगति रिपोर्ट भेजी गई या फिर केवल कागजों पर उपलब्धि दिखाकर अभियान को सफल घोषित कर दिया गया।

गर्मी में जंगलों में थे मवेशी,फिर गांव में टीकाकरण कैसे हो गया?

किसानों के अनुसार अभियान के दौरान अधिकांश ग्रामीण अपने मवेशियों को जंगल, चरागाह और खुले क्षेत्रों में चरने के लिए छोड़ देते हैं। कई पशु पूरे दिन गांव से बाहर रहते हैं और शाम को लौटते हैं, ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिन पशुओं की उस समय गांव में मौजूदगी ही नहीं थी,उनका टीकाकरण आखिर किस प्रकार कर दिया गया? यदि टीकाकरण दल गांव पहुंचा भी था,तो क्या उसने वास्तव में सभी पशुओं का इंतजार किया? या फिर बिना सत्यापन के ही आंकड़े तैयार कर लिए गए? ग्रामीणों का कहना है कि यदि पशु गांव में उपलब्ध नहीं थे,तो ऑनलाइन पोर्टल में उनके नाम किस आधार पर दर्ज किए गए? क्या किसी अधिकारी ने इन आंकड़ों का भौतिक सत्यापन किया था या केवल कागजी प्रक्रिया पूरी कर अभियान को सफल घोषित कर दिया गया?

क्या ऑनलाइन पोर्टल में फर्जी आंकड़े अपलोड किए गए?

पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऑनलाइन डेटा है। वर्तमान व्यवस्था में टीकाकरण के बाद पशुओं का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाता है, किसानों का आरोप है कि जिन पशुओं का टीकाकरण हुआ ही नहीं, उनके नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज कर दिए गए। यदि ऐसा हुआ है तो यह जानना आवश्यक होगा कि आंकड़े किस कर्मचारी ने दर्ज किए? किस अधिकारी ने उनका सत्यापन किया? क्या लाभार्थी पशुपालकों से कोई पुष्टि ली गई? क्या टीकाकरण का कोई भौतिक प्रमाण उपलब्ध है? यदि जांच में रिकॉर्ड और वास्तविकता में अंतर मिलता है, तो यह फर्जी रिपोर्टिंग का गंभीर मामला माना जा सकता है।

ग्रामवार भौतिक सत्यापन से सामने आ सकती है पूरी सच्चाई-

पशुपालकों और ग्रामीणों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रत्येक गांव में घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए, उनकी मांग है कि ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज प्रत्येक किसान और उसके पशुओं का मौके पर मिलान किया जाए। जिन पशुओं के टीकाकरण का दावा किया गया है, उनकी पुष्टि संबंधित पशुपालकों से कराई जाए, ग्रामीणों का मानना है कि यदि यह प्रक्रिया अपनाई गई तो कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में कितने पशुओं को टीका लगाया गया और कितने केवल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिए गए।

क्या मामला केवल खड़गवां तक सीमित है या पूरे एमसीबी जिले में?

क्षेत्र में चर्चा है कि यह मामला केवल खड़गवां विकासखंड तक सीमित नहीं हो सकता,कई पशुपालकों का कहना है कि जिले के अन्य विकासखंडों में भी इसी प्रकार की स्थिति हो सकती है,यदि पूरे एमसीबी जिले के टीकाकरण अभियान की स्वतंत्र जांच कराई जाए तो वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है,हालांकि इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

लाखों रुपये खर्च,लेकिन लाभ किसे मिला?

हर वर्ष शासन टीकाकरण अभियान पर बड़ी राशि खर्च करता है,वैक्सीन की खरीद,परिवहन,कोल्ड चेन,कर्मचारियों की तैनाती और अभियान संचालन पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं,यदि पशुओं तक टीका पहुंचा ही नहीं और रिकॉर्ड में शत-प्रतिशत उपलब्धि दर्शा दी गई,तो यह जांच का विषय होगा कि सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप हुआ या नहीं।

15 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों की भूमिका पर भी उठे सवाल-

स्थानीय लोगों का कहना है कि पशु चिकित्सा विभाग में कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी वर्षों से एक ही विकासखंड अथवा जिले में पदस्थ हैं, उनका मानना है कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने से जवाबदेही प्रभावित होती है और स्थानीय स्तर पर प्रभाव का दायरा बढ़ जाता है, ग्रामीणों ने ऐसे कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच तथा आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरण की मांग भी उठाई है, ताकि विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आए।

स्वतंत्र जांच की उठी मांग-ग्रामीणों और पशुपालकों ने राज्य शासन से मांग की है कि पूरे एमसीबी जिले में संचालित चापा-खुरा टीकाकरण अभियान की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, साथ ही ग्रामवार भौतिक सत्यापन, ऑनलाइन पोर्टल का ऑडिट, टीकाकरण रजिस्टर की जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए, उनका कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष ढंग से हुई तो टीकाकरण अभियान की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लग सकेगी।

प्रशासन का पक्ष-इस संबंध में पशु चिकित्सा विभाग के संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका,विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

दैनिक घटती-घटना के 10 बड़े सवाल

- क्या खड़गवां विकासखंड में वास्तव में 100 प्रतिशत चापा-खुरा टीकाकरण हुआ?
- क्या यही स्थिति पूरे एमसीबी जिले में भी है?
- जिन पशुओं को टीका नहीं लगा, उनके नाम रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हुए?
- ऑनलाइन पोर्टल में आंकड़े किस अधिकारी के सत्यापन के बाद अपलोड किए गए?
- क्या प्रत्येक गांव में टीकाकरण दल वास्तव में पहुंचा था?
- क्या शासन को वास्तविक प्रगति रिपोर्ट भेजी गई या केवल कागजी उपलब्धि दिखाई गई?
- अभियान में खर्च हुई सरकारी राशि का ऑडिट क्यों न कराया जाए?
- क्या ग्रामवार भौतिक सत्यापन पूरे मामले का खुलासा करेगा?
- वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों की भूमिका की जांच होगी?
- यदि अनियमितता सिद्ध होती है तो जिम्मेदारी किस अधिकारी की तय होगी?

चांग भखार की आराध्य देवी मां चांग माता के दरबार में उमड़ा जनसैलाब

जनहित संघ अंतर्गत पंडो विकास समिति के विशाल भोग-भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद,आस्था और सामाजिक समरसता का दिखा अनुपम संगम

-संवाददाता-

एमसीबी/भरतपुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। चांग भखार की आराध्य देवी मां चांग माता के पावन दरबार में रविवार को आस्था,श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। जनहित संघ अंतर्गत पंडो विकास समिति द्वारा मंदिर परिसर में विशाल भोग-भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के दूर-दराज गांवों से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मां चांग माता के दर्शन-पूजन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि,खुशहाली और शांति की कामना की तथा भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा,मां चांग माता के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। महिलाओं,युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। मंदिर परिसर में भक्ति और सेवा की भावना का ऐसा माहौल बना कि श्रद्धालुओं ने इसे क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का जीवंत उदाहरण बताया,भोग-भंडारे की शुरुआत जनहित संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष संवर्त कुमार रूप द्वारा मां चांग माता को विधि-विधान से खीर का भोग अर्पित कर की गई, पूजा-अर्चना के उपरांत भंडारे का शुभारंभ हुआ,जहां समिति के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों ने श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से प्रसाद वितरण किया,आयोजन के दौरान सेवा कार्य में युवाओं,माताओं एवं बहनों की सक्रिय भागीदारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सभी ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ व्यवस्थाओं का संचालन कर आयोजन को सफल बनाया,आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मां चांग माता का मंदिर चांग भखार क्षेत्र की लोकआस्था का प्रमुख केंद्र है, यहां वर्षभर श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है और दूर-दराज से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं,मान्यता है कि सच्चे मन से मां के चरणों में प्रार्थना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जनहित संघ अंतर्गत पंडो विकास

समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष सामाजिक समरसता, जनकल्याण और धार्मिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भोग-भंडारे का आयोजन किया जाता है, भंडारे में शामिल श्रद्धालुओं ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम समाज में भाईचारे,सहयोग और आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं। समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल,बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई तथा प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की गई थी,जिससे दूर-दूर से आए लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा,कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक सामाजिक कार्यकर्ता,जनप्रतिनिधि,वरिष्ठ नागरिक,युवा एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, सभी ने मां चांग माता के चरणों में प्रदेश और क्षेत्र की उन्नति, सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की कामना की। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं में सेवा और सहयोग की भावना भी देखने को मिली,जिसने पूरे कार्यक्रम को और अधिक गरिमामय बना दिया,भोग-भंडारे के सफल आयोजन ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि चांग भखार की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं आज भी समाज को एकजुट रखने का कार्य कर रही हैं,मां चांग माता के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार आस्था,सेवा भावना और सामाजिक सहभागिता ने इस आयोजन को भव्य, अनुकरणीय और अविस्मरणीय बना दिया।

95 वर्षीय वृद्ध दंपत्ति की मार्मिक पुकार : 'सरकार हमें इलाज और रहने के लिए एक घर दे दे'

धोवताल के बुजुर्ग दंपत्ति ने शासन-प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा जीवन,चल-फिर पाने में भी असमर्थ

-संवाददाता-

एमसीबी/भरतपुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत बरेल के निकट ग्राम पंचायत धोवताल के आश्रित ग्राम मंटोलिया में रहने वाले 95 वर्षीय वृद्ध समयलाल पंडों और उनकी पत्नी रुकमन पण्डो का जीवन आज उम्र के उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है,जहां उन्हें सबसे अधिक सहारे,सुरक्षा और उपचार की आवश्यकता है,लेकिन विडंबना यह है कि दोनों बुजुर्ग आज भी एक पक्के घर,समुचित इलाज और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। समयलाल पंडों ने भावुक स्वर में शासन-प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि अब उनकी उम्र इतनी अधिक हो चुकी है कि वे स्वयं चलकर अस्पताल तक भी नहीं जा सकते,लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति,शारीरिक कमजोरी और आर्थिक अभाव ने उनका जीवन बेहद कठिन बना दिया है,उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उन्हें इलाज की समुचित व्यवस्था और रहने के लिए एक पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए,ताकि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मिल सके,ग्रामीणों के अनुसार समयलाल पंडों और उनकी पत्नी लंबे समय से अत्यंत साधारण और कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं,कच्चे एवं जर्जर आशियाने में रहने के कारण बरसात के दिनों में पानी टपकने और गर्मी में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है,वृद्धावस्था के चलते दोनों पति-पत्नी दैनिक जीवन के सामान्य कार्य भी स्वयं नहीं कर पाते। कई बार उन्हें भोजन, दवा और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, ग्रामीणों का कहना है कि इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद यदि कोई बुजुर्ग दंपत्ति आज भी सरकारी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है, तो यह चिंता का विषय है,उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल मौके पर सर्वे कराया जाए और पात्रता के अनुसार दंपत्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा अन्य किसी आवासीय योजना का लाभ दिया जाए, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम नियमित रूप से उनके घर पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण करे तथा आवश्यक दवाएं और उपचार उपलब्ध कराया जाए,ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि यदि दंपत्ति किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन,खाद्यान्न योजना या अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं तो संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई कर उन्हें सभी पात्र योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करे। उनका कहना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य ऐसे ही जरूरतमंद और असहाय लोगों तक राहत पहुंचाना है।

मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा सवाल

धोवताल के इस 95 वर्षीय वृद्ध दंपत्ति की व्यथा केवल एक परिवार की समस्या नहीं, बल्कि यह सवाल भी है कि क्या समाज और शासन उन लोगों तक समय पर पहुंच पा रहे हैं जिन्हें सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता है, जीवनभर मेहनत करने के बाद आज समयलाल पंडों और उनकी पत्नी रुकमन पण्डो सम्मानजनक जीवन, सुरक्षित आश्रय और इलाज की उम्मीद में प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन इस मार्मिक गुहार पर कितनी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करता है तथा इस वृद्ध दंपत्ति को राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

राम कपूर के साक्षी तंवर के साथ ऑनस्क्रीन किस से बेहद नाराज थीं पत्नी गौतमी कपूर,बोलीं...उन्होंने प्रॉमिस तोड़ा

राम कपूर के लॉक अप 2 में विवादास्पद बयान के बाद,साक्षी तंवर के साथ उनके ऑन-स्क्रीन किस पर पत्नी गौतमी कपूर की नाराजगी का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है।
राम कपूर को लेकर लॉक अप सीजन 2 में काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। इस बात पर कंगना रनौत भी उन्हें लताड़ लगाती नजर आईं। राम कपूर ने हाल ही में शो में कहा है कि अगर पति-पत्नी के बीच सच्चा प्यार हो तो धोखा देने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं होता। ये बयान उन्होंने को-कंटेस्टेंट श्रेया कालरा के उस सवाल पर दिया, जिसमें उन्होंने पूछा कि 'अगर आपका पार्टनर चीट करे, तो क्या आप रिश्ता खत्म करेंगे'? अब पार्टनर को चीट करने वाले इस बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।

वायरल हो रहा राम कपूर का पुराना वीडियो

अब इस बीच राम कपूर का एक पुराना वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साक्षी तंवर के साथ अपने वायरल किस पर पत्नी गौतमी कपूर के रिएक्शन की बात बोली थी। नयनदीप रक्षित से बात करते हुए राम ने बताया था कि साक्षी के साथ किया गया किस, उनका पहला ऑन-स्क्रीन किस नहीं था। उन्होंने कहा, साक्षी तंवर से पहले भी मैंने कैमरे पर दो और एक्टर्स को किस किया था,लेकिन पता नहीं क्यों, तीसरे वाले से उन्हें परेशानी हुई।

क्यों नाराज थीं गौतमी कपूर?

उस समय उनके नाराज होने की वजह बताते हुए गौतमी ने माना कि उनका रिएक्शन प्यार और पजेसिवनेस दोनों की वजह से था। गौतमी ने कहा कि एक एक्ट्रेस होने के बावजूद इस चीज ने पता नहीं क्यों उन्हें हर्ट किया। गौतमी ने कहा कि सीन से ज्यादा दुःख उन्हें इस बात का था कि राम कपूर ने उन्हें इस बारे में पहले नहीं बताया।
गौतमी ने कहा,उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब मैंने पहले किसिंग सीन देखे थे,तो मैंने साफ-साफ कह दिया था, तुम कभी भी ऑन-स्क्रीन किस नहीं करोगे। तुम बाकी कुछ भी कर सकते हो। हमारी यही डील थी। यहां पर उन्होंने अपनी बात नहीं रखी।
हालांकि राम कपूर का कहना है कि उनकी वाइफ गौतमी लॉक अप 2 को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उन्होंने ही उन्हें आगे बढ़ने का इशारा दिया।

फिल्म इश्कनामा से शहनाज गिल की पहली झलक जारी,24 जुलाई को होगी रिलीज

शहनाज गिल को लोकप्रियता अब सिर्फ पंजाबी फिल्म जगत तक सीमित नहीं रही है। हिंदी पट्टी के दर्शक भी उनके जबरा फैन बन चुके हैं। फिलहाल अभिनेत्री अपनी आगामी फिल्म इश्कनामा को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने फिल्म से अपनी पहली झलक जारी कर दी है जिसने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। फिल्म के निर्देशन की कमान अरविंदर खैरा ने संभाली है। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित एक रोमांटिक ड्रामा है।
इश्कनामा के पोस्टर में शहनाज दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने चेहरे को दुपट्टे से छिपा रखा है। दूसरी तस्वीर में वह जय रंधावा के साथ नजर आ रही हैं, जो फिल्म के अभिनेता हैं। पोस्टर के साथ उन्होंने कैप्शन दिया, मेरी आने वाली फिल्म की पहली तस्वीरज ..इश्कनामा सच्चे प्रेमियों निम्मा-नसिमा की सच्ची कहानी 24 जुलाई, 2026 को दुनियाभर में रिलीज हो रही है। बता दें...शहनाज को बिग बॉस 13 से लोकप्रियता मिली थी।

फिल्म तेरा यार हूं मैं की नई रिलीज तारीख का ऐलान,24 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

बॉलीवुड की धमाल फ्रैंचाइजी के निर्देशक इंद्र कुमार के बेटे,अमन इंद्र कुमार अपनी पहली फिल्म तेरा यार हूं मैं को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी यह एक भावनात्मक रोमांटिक ड्रामा कहानी है। फिल्म में अमन के साथ मुख्य किरदार में आकांक्षा शर्मा नजर आएंगी, जो हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू कर रही हैं। ताजा अपडेट है कि फिल्म की रिलीज तारीख एक बार फिर से बदल दी गई है। मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक्स पर तेरा यार हूं मैं की नई रिलीज तारीख का ऐलान किया है। पोस्ट के अनुसार,फिल्म अब अपनी तय रिलीज तारीख (31 जुलाई, 2026) से एक हफ्ते पहले दस्तक देगी। नई तारीख के साथ, फिल्म 24 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने अमन और आकांक्षा पर फिल्माए गए टाइटल ट्रैक की एक झलक भी जारी है। फिल्म में

परेश रावल भी अहम किरदार में दिखेंगे। इससे पहले मेकर्स ने फरवरी में फिल्म की घोषणा करते हुए इसका फर्स्ट लुक जारी किया था। तब मेकर्स फिल्म को 22 मई को रिलीज करने वाले थे। लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट बदल दी है। फिल्म का जो पोस्टर जारी किया गया है,उसमें फिल्म के लीड कलाकार अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा नजर आ रहे हैं। व्हाइट बैकग्राउंड में दोनों के चेहरों का क्लोज अप शॉट है, जिसमें दोनों एक-दूसरे में खोए नजर आ रहे हैं। अभी तक फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

शाहिद कपूर ने 18 करोड़ रुपये में साइन की कॉमेडी फिल्म अदल बदल,अभिनेत्री जाह्नवी कपूर संग बनेगी जोड़ी

शाहिद कपूर को आखिरी बार फिल्म कॉकटेल 2 में देखा गया,जिसमें वह रश्मिका मंदाना और कृति सैनन के साथ इश्क लड़ाते हुए नजर आए। खबर है कि अब उन्होंने अपनी अगली फिल्म की तरफ कदम बढ़ा दिया है,जो सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अमित रविंद्रनाथ शर्मा द्वारा निर्देशित इस कॉमेडी फिल्म के लिए शाहिद ने 18 करोड़ रुपये की डील भी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि वह फिल्म की तैयारी में जल्द ही जुट जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक,फिल्म का शीर्षक अदल बदल है और इसकी शूटिंग अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी। सूत्र ने कहा, फिल्म का निर्माण सुनीर खेत्रपाल और अमेजन एमजीएम मिलकर कर रहे हैं। इसकी शूटिंग अक्टूबर, 2026 में शुरू होगी। बजट को लेकर परियोजना लेने को लेकर कुछ दुविधाएं थीं,लेकिन अब सब ठीक है। शाहिद ने परियोजना के लिए 18 करोड़ रुपये की फीस ली है और फिल्म के मुनाफे की स्थिति में उन्हें एक अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। सूत्र ने आगे बताया कि फिल्म में शाहिद के साथ जाह्नवी कपूर मुख्य किरदार में होंगी। यह पहली बार होगा, जब दोनों साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले,शाहिद की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (2024) में जाह्नवी ने कुछ मिनट का कैमियो किया था। बताया जा रहा है कि अदल बदल आत्माओं के आदान-प्रदान की अवधारणा पर आधारित मजेदार कॉमेडी होगी। फिलहाल,शाहिद अपनी आगामी सीरीज फर्जी 2 की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं।

टॉक्सिक का नया टीजर जारी,लेडीज एंड लेडीज के साथ एक्शन करते दमदार लगे यश

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक का नया टीजर जारी हो गया है। फैंस की नाराजगी को दूर करते हुए निर्माताओं ने इस बार सभी हसीनाओं का दीदार टीजर में करा दिया है। लेडीज एंड लेडीज के नाम से आए इस धमाकेदार टीजर में कियारा आडवाणी नादिया का किरदार निभाती दिखीं और यश के साथ स्क्रीन साझा करेंगी। वहीं नयनतारा (गंगा),तारा सुतारिया (रेबिका), रुक्मिणी वसंत (मेलिसा) और हुमा कुरैशी (एलिजाबेथ) के किरदारों में नजर आई हैं। टीजर

की शुरुआत एक चेतावनी के साथ होती है। इसके बाद सभी हसीनाओं की एक-एक झलक दिखाई गई है। यह साबित करता है कि फिल्म सिर्फ हीरो-केंद्रित एक्शन नहीं है, बल्कि इसमें अभिनेत्रियां भी खतरनाक और महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं। वहीं यश दमदार एक्शन करते हुए नजर आए हैं। इसकी कहानी गोवा में ड्रग कार्टेल और खतरनाक स्मगलिंग के इर्द-गिर्द बुनी गई है। केवीएन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित टॉक्सिक 26 अगस्त, 2026 को रिलीज होगी।

फिल्मों के चुनाव को लेकर चेतना पांडे का बेबाक बयान,स्क्रीन टाइम नहीं,दमदार किरदार चाहिए...

अभिनेत्री चेतना पांडे को हालिया रिलीज फिल्म हॉन्टेड 3डीः इकोज ऑफ द पास्ट से दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस सफलता के बीच चेतना ने करियर,फिल्मों के चुनाव और भविष्य की योजनाओं को लेकर कहा कि अब वह केवल ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, जो उन्हें एक कलाकार के तौर पर आगे बढ़ाएं और दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ें।

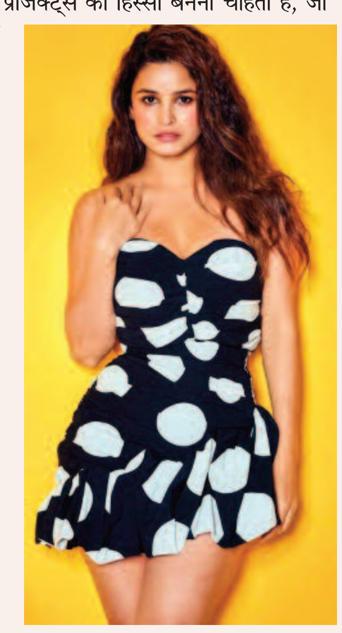

चेतना पांडे ने कहा,करियर के इस पड़ाव पर मैं खुद को किसी एक तरह के किरदार या फिल्म शैली तक सीमित नहीं रखना चाहती। हॉरर फिल्म में काम करने के बाद मुझे इस शैली की ताकत का एहसास हुआ है, इसलिए मैं आगे भी हॉरर फिल्मों में काम करना चाहूंगी। मैं सिर्फ इसी शैली तक सीमित नहीं रहना चाहती। एक कलाकार के रूप में मेरा सबसे बड़ा सपना खुद को और अपने दर्शकों को लगातार नए रूप में चौंकाना है। अभिनेत्री ने कहा, मैं ऐसा किरदार निभाना चाहती हूं, जो मुझे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौती दे और मुझे आगे बढ़ाता रहे। चाहे कोई बड़ी कमर्शियल फिल्म हो, थ्रिलर हो या फिर बायोपिक,मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने यह बात रखती है कि मेरा किरदार दर्शकों के मन में लंबे समय तक बना रहे।
चेतना ने कहा, मुझे फिल्म में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए। मैं ऐसे रोल्स को प्राथमिकता देती हूं, जिनकी कहानी में दम हो और जो कुछ कहने की ताकत रखते हों। मैं केवल ग्लैमर दिखाने वाली भूमिकाओं की बजाय ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हूं,जो लोगों को सोचने पर मजबूर करें। हर नया प्रोजेक्ट मुझे पहले किए गए काम से आगे ले जाए और कुछ नया सिखाए। चेतना ने कहा, मैं अभी भी इस पूरे अनुभव को समझने और महसूस करने की कोशिश कर रही हूं। जब कोई कलाकार लंबे समय तक किसी फिल्म पर मेहनत करता है, कई तरह की चुनौतियों का सामना करता है और यह उम्मीद करता है कि दर्शक उसके काम को पसंद करेंगे, तब सफलता मिलने के बाद उस पल को तुरंत समझ पाना आसान नहीं होता। हॉन्टेड 3डी फिल्म की सफलता पर खुशी जताते हुए चेतना ने कहा, पिछले कुछ दिन जश्न से ज्यादा आभार के रहे हैं। मैंने सबसे पहले परिवार, दोस्तों और उन लोगों से बात की, जिन्होंने इस सफर में हर कदम पर मेरा साथ दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे करीबी लोग मेरी सफलता से खुश हैं।

खेल समाचार

भारत के श्रीलंका दौरे का शेड्यूल घोषित

भारतीय टीम अगस्त में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरे करेगी...टीम 9 साल बाद श्रीलंका की धरती पर टेस्ट मैच खेलने जाएगी...अभी तक दोनों टीमों के बीच वहां 24 मैच हुए हैं...

नई दिल्ली,02 जुलाई 2026। भारत अगस्त 2026 में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा। श्रीलंका क्रिकेट ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 चक्र का हिस्सा होगी। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त के बीच गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होगा।

श्रीलंका में भारत का रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने पहली बार 1985 में टेस्ट मैच खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा किया था। तब से अभी तक दोनों टीमों के बीच वहां 24 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। इसमें भारत ने 9 में जीत हासिल की है जबकि श्रीलंका को 7 जीत मिली है। वहीं 8 मैच ड्रॉ रहे हैं। श्रीलंका में हुए आखिरी 5 टेस्ट मैचों में भारत को ही जीत मिली है। 2017 में टीम ने आखिरी बार यहां का दौरा किया था तो विराट कोहली की कप्तानी में सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करने में सफल रही थी।

तीन सीरीज जीत चुकी भारतीय टीम

भारतीय टीम ने अभी तक श्रीलंका में 8 टेस्ट सीरीज खेली है। इसमें टीम को 2017 के अलावा 2015 और 1993 में भी जीत मिली थी। 2015 में भी विराट कोहली ही कप्तान थे। पहले मैच में हार के बाद भारत ने अगले दोनों मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लिया था। वहीं 1985, 2001 और 2008 में भारतीय टीम हार गई। 1997 और 2010 में खेली गई सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी।

टेस्ट चैंपियनशिप के लिए सीरीज अहम

भारत और श्रीलंका के लिए यह दो मुकाबलों की सीरीज बेहद अहम है। दोनों टीमें डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में ऊपर चढ़ना चाहती हैं। मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र की प्वाइंट्स टेबल में, शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 9 मुकाबलों के बाद 48.15 के प्वाइंट्स प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है। वहीं, श्रीलंका 44.44 के पीसीटी के साथ छठे पायदान पर है।

ग्रैंड चेस टूर क्रोएशिया में पहले दिन प्रग्गनानंदा का शानदार आगाज,छठे स्थान पर रहे गुकेश

जाग्रेब ,02 जुलाई 2026। ग्रैंड चेस टूर 2026 के तीसरे इवेंट सुपर रैपिड और ब्लिट्ज क्रोएशिया में भारतीय खिलाड़ियों की शुरुआत अलग-अलग रही। युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रग्गनानंदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले दिन संयुक्त दूसरे स्थान पर जगह बनाई, जबकि मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश छठे स्थान पर रहे।प्रग्गनानंदा ने पहले मुकाबले में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर शानदार शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव के खिलाफ ड्रॉ खेला। वहीं, दिन के तीसरे और आखिरी राउंड में उनका मुकाबला गुकेश से हुआ, जो ड्रॉ पर खत्म हुआ। पहले दिन के बाद प्रग्गनानंदा के 6 में से 4 अंक हैं और वह संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। दूसरी ओर, गुकेश का पहला मैच अच्छा नहीं रहा। उन्हें मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने दूसरे राउंड में इवान सारिक को हराकर शानदार वापसी की। तीसरे राउंड में प्रग्गनानंदा के खिलाफ उनका मुकाबला ड्रॉ रहा। तीन राउंड के बाद गुकेश के 6 में से 3 अंक हैं और वह छठे स्थान पर हैं। रैपिड सेक्शन के अभी छह राउंड और खेले जाने बाकी हैं। पहले दिन के बाद फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा 5 अंकों के साथ अकेले शीर्ष पर हैं। उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए बढ़त बनाई। खास बात यह है कि कुछ सप्ताह पहले टखने की चोट के कारण उन्हें रोमानिया में ग्रैंड चेस टूर का एक इवेंट बीच में छोड़ना पड़ा था। अब उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लीड हासिल कर ली है। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला अनीश गिरी से ड्रॉ रहा, जिससे उनकी बढ़त बरकरार रही। अन्य मुकाबलों में विंसेंट कीमर ने नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराकर जीत दर्ज की। वहीं, बोगदान-डैनियल डेक ने इवान सारिक को हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की। मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। इस टूर्नामेंट में दो प्रारूप खेले जा रहे हैं। पहले 9 राउंड का सुपर रैपिड टूर्नामेंट होगा, जिसमें हर खिलाड़ी को 25 मिनट का समय और हर चाल पर 10 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके बाद 18 राउंड का ब्लिट्ज टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें हर खिलाड़ी को 5 मिनट और हर चाल पर 2 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलेगा। रैपिड में जीत पर 2 अंक और ड्रॉ पर 1 अंक मिलता है, जबकि ब्लिट्ज में जीत पर 1 अंक और ड्रॉ पर आधा अंक दिया जाता है।

खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के चयन का आधिकारिक ढांचा जारी किया

नई दिल्ली,02 जुलाई 2026। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के चयन का आधिकारिक ढांचा जारी किया है। इसमें एथलीटों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ़ के चयन और मंजूरी की चरण-दर-चरण प्रक्रिया बताई गई है। इस ढांचे में यह साफ़ किया गया है कि केवल वे ही लोग आधिकारिक भारतीय दल का हिस्सा माने जाएंगे जिनके नाम एमवाईएएस द्वारा जारी मंजूरी आदेश में शामिल हैं। खास बात यह है कि 2026 के एशियाई खेल जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होंगे ।एशियाई खेलों के लिए एथलीटों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ़ का चयन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी नीतिगत ढांचे के अनुसार किया जाता है।

रणविजय सिंहदेव
पूर्व राज्यसभा सांसद

नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई के जिम्मे

क्या जांच केवल दो दर्ज अपराधों तक सीमित रहेगी या पुलिस की भूमिका पर भी होगा जांच का फोकस?

छत्तीसगढ़ शासन
गृह (सी- अनुभाग) विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
-0-
//अधिसूचना//
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक30-06-2026
File No.:GENCOR-35/5403/2025-HOME SECTION :: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 सन 1946) की धारा 6 के तहत [illegible] थाना - सोनहत, जिला - कोरिया, छत्तीसगढ़, [illegible] 65/2026 [illegible] 66/2026 [illegible]
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(आर.पी. [illegible])
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग

ज्योत्सना महंत
लोकसभा सांसद, कोरबा

राज्य सरकार ने दर्ज दो अपराधों को लेकर सीबीआई को लिखा पत्र

पुलिस की भूमिका, लापरवाही और नेताओं के संरक्षण का कोई उल्लेख नहीं

क्या सीबीआई मृतकों के परिजनों से भी लेगी आवेदन, क्या उनके पक्ष पर भी होगी जांच केंद्रित?

सीबीआई बाल की खाल निकालकर रहेगी, सभी आरोपियों सहित उन्हें संरक्षण देने वालों तक पहुंच जाएगी

17वें दिन राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद सीबीआई जांच के आदेश, अब सबकी निगाहें जांच के दायरे और सीबीआई की पहली कार्रवाई पर

नौगई तिहरे हत्याकांड : सीबीआई जांच पर टिकी उम्मीदें

अब पुलिस की भूमिका भी होगी बेनकाब ?

राज्य सरकार की अधिसूचना में केवल दो अपराध क्रमांक के अनुसंधान का उल्लेख, अब नजर इस बात पर कि क्या सीबीआई पूरे घटनाक्रम, पुलिस की भूमिका और कथित संरक्षण के आरोपों की भी करेगी पड़ताल

नौगई हत्याकांड में सीबीआई जांच शुरू होने की तैयारी क्या पुलिस और संरक्षण देने वालों तक पहुंचेगी जांच? सीबीआई के हवाले नौगई हत्याकांड, अब सबसे बड़ा सवाल– क्या केवल अपराध या पूरी साजिश की होगी जांच?

नौगई हत्याकांड : सीबीआई जांच का रास्ता साफ, अब सबकी नजर जांच के दायरे और पहली कार्रवाई पर

सीबीआई जांच के जिम्मे नौगई हत्याकांड क्या दर्ज अपराधों से आगे बढ़ेगी जांच की दिशा?

रवि सिंह

कोरिया,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी होने के बाद जहां पीड़ित परिवार और समाज में निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी है,वहीं अब एक नया और महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आ गया है, सवाल यह है कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) केवल थाना सोनहत में दर्ज दो अपराधों की विवेचना तक सीमित रहेगी, या फिर पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की भूमिका, कथित लापरवाही, संभावित संरक्षण,जनप्रतिनिधियों से जुड़े आरोप और अन्य सभी पहलुओं की भी जांच करेगी 30 जून 2026 को गृह (सी-अनुभाग) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 की धारा 6 के तहत थाना सोनहत में दर्ज अपराध क्रमांक 65/2026 एवं 66/2026 के अनुसंधान के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सीबीआई) को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की सहमति दी गई है, अधिसूचना में इन दोनों अपराधों के अनुसंधान का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की भूमिका, विभागीय लापरवाही या अन्य संभावित आरोपों का अलग से उल्लेख नहीं है,यही कारण है कि अब इस अधिसूचना की भाषा और जांच के वास्तविक दायरे को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

क्या केवल दो एफआईआर की होगी जांच?

कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी भी सीबीआई जांच का आधार राज्य सरकार द्वारा संदर्भित प्रकरण होता है, हालांकि विवेचना के दौरान यदि ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो मूल अपराध से जुड़े हों,तो जांच एजेंसी उन पहलुओं तक भी पहुंच सकती है, यही कारण है कि नौगई मामले में लोगों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि सीबीआई केवल दर्ज अपराधों के तथ्यों तक सीमित रहेगी या विवेचना के दौरान सामने आने वाले अन्य तथ्यों पर भी कार्रवाई करेगी, थाना सोनहत में 16 जून को पहली एफआईआर आरोपी पक्ष के एक युवक की शिकायत पर दर्ज हुई थी, इसके अगले दिन 17 जून को जघन्य वारदात के बाद मृतक भरत सिंह लल्ला के पुत्र की ओर से दूसरी एफआईआर दर्ज कराई गई,इन्हीं दोनों अपराधों को अधिसूचना में सीबीआई जांच के लिए संदर्भित किया गया है।

परिजनों की मांग केवल हत्या की जांच नहीं,पूरे घटनाक्रम की जांच

घटना के बाद से मृतकों के परिजन लगातार यह कहते रहे हैं कि उनकी लड़ाई केवल आरोपियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है,उनका कहना है कि यदि किसी स्तर पर पुलिस की लापरवाही,संरक्षण,प्रभाव या गलत निर्णय के कारण यह वारदात हुई है तो उसकी भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, परिजनों ने पूर्व में राज्य शासन,पुलिस महानिदेशक सरगुजा आईजी और अन्य अधिकारियों को दिए गए ज्ञापनों में कई मांगें रखी थीं, इनमें पुलिस अधिकारियों की भूमिका की विभागीय जांच,कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच, मोबाइल लोकेशन,इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का परीक्षण, कथित आत्मसमर्पण की परिस्थितियों की जांच तथा संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग भी शामिल थी,अब जबकि सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है,परिजनों की उम्मीद है कि जांच एजेंसी उनके आवेदन और उपलब्ध साक्ष्यों को भी गंभीरता से सुनेगी।

क्या पुलिस की भूमिका भी होगी जांच का हिस्सा?

घटना के बाद से लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा कि पुलिस को दोनों पक्षों के बीच तनाव की जानकारी पहले से थी,यह भी कहा गया कि विवाद की सूचना मिलने के बाद पुलिस दिनभर सक्रिय रही,लेकिन इसके बावजूद रात में इतनी बड़ी वारदात हो गई, स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी लगातार उठाया जाता रहा कि यदि संभावित बड़ी घटना की आशंका थी तो पुलिस की निगरानी दोनों पक्षों पर समान रूप से क्यों नहीं रही, कुछ लोगों ने थाना प्रभारी की अनुपस्थिति,प्रारंभिक पुलिस कार्रवाई और अधिकारियों द्वारा दिए गए शुरुआती बयानों पर भी प्रश्न उठाए,इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारी भी सार्वजनिक रूप से अपने स्तर पर कार्रवाई को नियमसम्मत बताते रहे हैं। अब यह देखना होगा कि सीबीआई जांच के दौरान इन पहलुओं पर भी कोई तथ्यात्मक परीक्षण होता है या नहीं।

जय प्रकाश शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट बिलासपुर

सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर टिकी उम्मीदें...

नौगई हत्याकांड को लेकर जिले में लगातार यह चर्चा रही है कि मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), लोकेशन डेटा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच से पूरे घटनाक्रम की कई परतें सामने आ सकती हैं, परिजनों और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि घटना से पहले, घटना के दौरान और उसके बाद हुई बातचीत तथा संपर्कों की निष्पक्ष जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो सकता है कि घटना पूरी तरह अचानक हुई थी या पूर्व नियोजित थी,हालांकि इन दावों और आशंकाओं की पुष्टि अभी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा नहीं की गई है।

ज्योत्सना महंत ने कहा-न्याय सबसे महत्वपूर्ण

कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात के दौरान कहा कि इस जघन्य घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है, उन्होंने कहा कि जांच का उद्देश्य पूरी सच्चाई सामने लाना होना चाहिए और निष्पक्ष जांच से ही लोगों का विश्वास कायम रहेगा, उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं।

क्या सीबीआई परिजन पक्ष का आवेदन भी लेगी?

पीड़ित परिवार का कहना है कि अब वे अपने सभी दस्तावेज,आवेदन,शिकायतें और उपलब्ध साक्ष्य सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत करेंगे,उनका मानना है कि केवल पुलिस केस डायरी के आधार पर ही नहीं,बल्कि पीड़ित पक्ष की आपत्तियों,शिकायतों और तथ्यों पर भी जांच आगे बढ़नी चाहिए,कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, जांच एजेंसी जांच के दौरान संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर सकती है और उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का परीक्षण भी कर सकती है, हालांकि जांच की प्रक्रिया और दायरा एजेंसी स्वयं उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर तय करती है।

रणविजय सिंहदेव बोले...सीबीआई बाल की खाल तक निकालेगी...

मृतकों के परिजनों से मिलने बैकुंठपुर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा किया जाना महत्वपूर्ण निर्णय है,उन्होंने विश्वास जताया कि सीबीआई केवल औपचारिक जांच नहीं करेगी,बल्कि मामले की तह तक पहुंचेगी, उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति,अधिकारी या अन्य किसी स्तर पर किसी प्रकार की भूमिका या संरक्षण सामने आता है तो जांच एजेंसी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उस तक भी पहुंचेगी,उन्होंने यह भी कहा कि घटना के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों के प्रारंभिक बयान भी चर्चा का विषय रहे हैं और यदि आवश्यकता हुई तो उनकी भी जांच होनी चाहिए।

अब सीबीआई की पहली कार्रवाई पर टिकी हैं निगाहें- अधिसूचना जारी होने के बाद अब सबसे बड़ा इंतजार इस बात का है कि सीबीआई कब औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में लेती है, इसके बाद एजेंसी घटनास्थल का निरीक्षण,केस डायरी का परीक्षण, दस्तावेजों का अधिग्रहण,गवाहों के बयान और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर सकती है,पूरे प्रदेश की निगाहें अब इस बात पर हैं कि सीबीआई की विवेचना का वास्तविक दायरा क्या होगा। क्या जांच केवल दो दर्ज अपराधों के अनुसंधान तक सीमित रहेगी,या फिर विवेचना के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों,पुलिस की भूमिका,इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों,कथित संरक्षण और अन्य संबंधित पहलुओं का भी परीक्षण करेगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर अब केवल सीबीआई की जांच और उसके निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता जय प्रकाश शुक्ला की राय: केवल अपराध की जांच नहीं,पूरी सच्चाई के लिए न्यायिक जांच अधिक प्रभावी

हाईकोर्ट बिलासपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता जय प्रकाश शुक्ला ने नौगई ट्रिपल हत्याकांड की जांच को लेकर कहा कि यदि उद्देश्य केवल दर्ज अपराधों की जांच,साक्ष्य संकलन और आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना है,तो राज्य पुलिस भी इसके लिए सक्षम एजेंसी है,उन्होंने कहा कि वर्तमान अधिसूचना के अनुसार सीबीआई का अन्वेषण मुख्य रूप से दर्ज अपराधों के तकनीकी पहलुओं और साक्ष्यों तक सीमित रहेगा, न्होंने कहा कि यदि इस जघन्य वारदात के पीछे किसी व्यापक साजिश, प्रशासनिक चूक,संरक्षण या अन्य संवेदनशील पहलुओं को सामने लाना उद्देश्य है,तो उनकी विधिक राय में न्यायिक जांच अधिक प्रभावी विकल्प होती। न्यायिक जांच का दायरा व्यापक होता है और उसमें अधिकारियों की भूमिका,निर्णय प्रक्रिया तथा पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा की जा सकती है। जय प्रकाश शुक्ला के अनुसार,ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक जांच वास्तविक तथ्यों तक पहुंचने और जनता के मन में उठ रहे सभी सवालों का समग्र उत्तर देने में अधिक सक्षम साबित हो सकती है।

300 से अधिक होटलों में ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठगबाज रायपुर पुलिस की गिरफ्त में

रायपुर,02 जुलाई 2026। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देशभर के 300 से अधिक होटलों में ठगी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 10 से अधिक राज्यों में मामले दर्ज हैं और वह लगभग 15 वर्षों तक देश के विभिन्न जेलों में निरुद्ध रह चुका है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला तथा पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) उमेश प्रसाद गुप्ता के संयुक्त निर्देशन में की गई। आरोपी ने रायपुर के थाना तेलीबांधा क्षेत्र स्थित होटल हयात में ठगी की

घटना को अंजाम दिया था,जिसके बाद उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 284/26 धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में प्रार्थी सूरज सिंह, जो होटल हयात में सिक्योरिटी इंचार्ज के पद पर कार्यरत हैं,ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जून 2026 को भीमसेंट जॉन नामक व्यक्ति होटल के एक कमरे में ठहरा था। 27 जून 2026 की सुबह लगभग 07:44 बजे वह बिना चेक-आउट प्रक्रिया पूरी किए होटल से चला गया और 63,755 रुपये का बकाया बिल अदा नहीं किया। इसके अलावा उसने होटल से किराए पर लिया गया लगभग 1,48,000 रुपये मूल्य का लैपटॉप भी साथ ले लिया। होटल प्रबंधन द्वारा कई बार उसके मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने का प्रयास किया गया,लेकिन दोनों नंबर बंद मिले। आरोपी ने न तो कोई संपर्क किया और न ही बिल भुगतान या लैपटॉप लौटाने का प्रयास किया। इसके बाद होटल प्रबंधन ने थाना तेलीबांधा में शिकायत दर्ज कराई। घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला...सहायक प्राध्यापकों के 700 पदों पर भर्ती

रायपुर,02 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। बैठक का सबसे अहम फैसला सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर तत्काल प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का है। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग के अन्य खाली पदों को भरने के लिए भी सरकार को जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। वहीं, सीजीपीएससी के माध्यम से चल रही प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक कसावट: 31 जुलाई तक सभी स्नातक कॉलेजों को मिलेंगे प्राचार्य : महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता और प्रशासनिक सुदृढ़ता लाने के लिए मंत्री टंक राम वर्मा ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि 31 जुलाई 2026 तक सभी स्नातक कॉलेजों में नियमित प्राचार्यों की पदोन्नति का कार्य हर हाल में पूर्ण हो जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट विजन है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रदेश का कोई भी सरकारी कॉलेज बिना नियमित प्राचार्य के न रहे। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के एजेंडे का हिस्सा है, जिसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

कर्मचारियों और अतिथि प्राध्यापकों को बड़ी राहत : बैठक में विभाग के कर्मचारियों और प्राध्यापकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई संवेदनशील फैसले लिए गए। सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति के लिए पुराने नियमों (1990 के नियम) को आधार बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे उनकी वरिष्ठता सुरक्षित बनी रहेगी। वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान की सूचियां भी जल्द जारी कर दी जाएंगी। अतिथि प्राध्यापकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर बनी कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार तुरंत कार्रवाई करने जा रही है। साथ ही, सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां अब 'राज्य कर्मचारी चयन आयोग' के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी।

ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष अंग्रेजी संचार कोर्स : वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी अंचल के छात्रों के लिए एक अभिनव पहल की है। कॉलेजों में '90 घंटे, 90 दिन' का विशेष इंग्लिश कम्यूनिकेशन कोर्स शुरू किया जाएगा, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों का संकोच दूर हो सके। इसके साथ ही विभाग ने पूरे प्रदेश में शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। वित्तीय प्रबंधन में शुचिता बरतते हुए बजट आवंटन से पहले प्रशासनिक अनुमोदन को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्नातकोत्तर स्तर पर विस्तार : छत्तीसगढ़ अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की सफलता के बाद, अब इसे स्नातकोत्तर स्तर पर भी विस्तार देने की तैयारी है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)